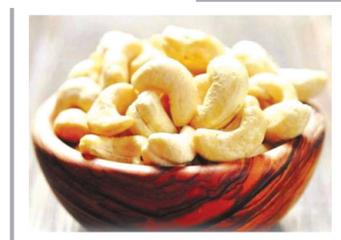


समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6» उत्तम औषधि है काजू

जम्मू की सीमाएँ तस्करी का बनी केंद्र

जम्मू। जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से तस्करी की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। और आपको बता कि ये घटनाएँ पाकिस्तान से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं बल्कि जम्मू की सीमाओं पर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से हमने राज्य में कई तरह के परिवर्तन देखे हैं। जहाँ पहले युवाओं को आतंकवादी विचार धारा वाले लोगों ने पत्थर बाजी और आतंकवादी गतिविधियों में फँसाया हुआ था वहीं इस तरह की गतिविधियाँ अब कुछ प्रतिशत कम हुई हैं लेकिन इसके साथ-साथ कुछ अन्य समस्याओं से भी जम्मू कश्मीर जूझ रहा है।

कुछ रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि जम्मू की सीमाएँ मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बनी हुई हैं। वहीं बात करें कि सीमा पार तस्करी करने वाले कौन लोग हैं। तो कुछ आंकड़ों के अनुसार इन काम के लिए अब महिलाओं को रखा जा रहा है। इस और अन्य नशीले पदार्थों



की तस्करी करने के मामले में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तस्करी करने के लिए महिलाओं को इस लिए भी शामिल किया जा रहा है कि इनपर शक कम किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की आमद में तेजी से वृद्धि और सुरक्षा बलों तथा नागरिकों पर हमले करने के लिए धन जुटाने में उनके उपयोग के विश्लेषण के बाद नए तथ्य सामने आए हैं। पिछले तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में उच्च तीव्रता वाले आतंकवादी हमलों में वृद्धि के लिए मादक पदार्थ प्रमुख योगदानकर्ताओं में से

एक रहे हैं और इस खतरे पर अंकुश लगाना सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी खबर के अनुसार उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की तुलना में जम्मू क्षेत्र से लगी सीमाएँ जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी में प्रमुख भूमिका निभाती हैं और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए महिलाओं की तैनाती बढ़ रही है। यह जानकारी केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को दी। लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा जम्मू-कश्मीर में

तस्करी की घटनाओं में पांच वर्षों में 30 प्रतिशत की वृद्धि अगर अधिकारियों के बयानों को देखा जाए तो आंकड़े कहते हैं कि कश्मीर में मादक पदार्थों की खपत में पिछले पांच वर्षों में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तक कई मामले दर्ज किए जाने के बावजूद, केवल कुछ तस्करी ही पकड़े गए हैं।

एक सूत्र ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में एक नशीले पदार्थ विक्रेता औसतन 3 लाख रुपये तक नकद कमाता है। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास तत्तानी और अब्बासपुर, जम्मू में चिनाब नदी के किनारे और सांबा के पास पंगदौर और घगवाल जैसे इलाके जम्मू बेल्ट के उन इलाकों में से हैं, जहाँ जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। कश्मीर घाटी में, सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों की तस्करी बारामुल्ला और कुपवाड़ा क्षेत्रों में होती है, खासकर शमशावारी रिज के करीब स्थित इलाकों में हुई।

कांग्रेस में बढ़त रही बगावत के कारण क्या बागी अबकी बार भी हाथ में नहीं आने देंगे सत्ता?

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के हाथ में हरियाणा की सत्ता आएगी या नहीं इसका जवाब 5 अक्टूबर को मतदान और 8 को मतगणना के बाद ही मिल सकेगा। फिलहाल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में जुटी है। फिलहाल पार्टी ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 41 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। शेष 49 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान भी होने ही वाला है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के 41 नाम घोषित होते ही भगदड़ मच गई। कई नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में चले गए। कांग्रेस में बगावत बढ़ती गई तो दस साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी का ख्वाब अबकी बार भी अधूरा ही रह जाएगा।

हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, बगावत बरोदा में इंदुराज सिंह नरवाल को टिकट मिलने से जितेंद्र हुड्डा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे डॉ. कपूर नरवाल ने तो नरवाल की वजह से पार्टी ही छोड़ दी। जुलाना में विनेश फोगट की उम्मीदवारी के कारण परमंद सिंह



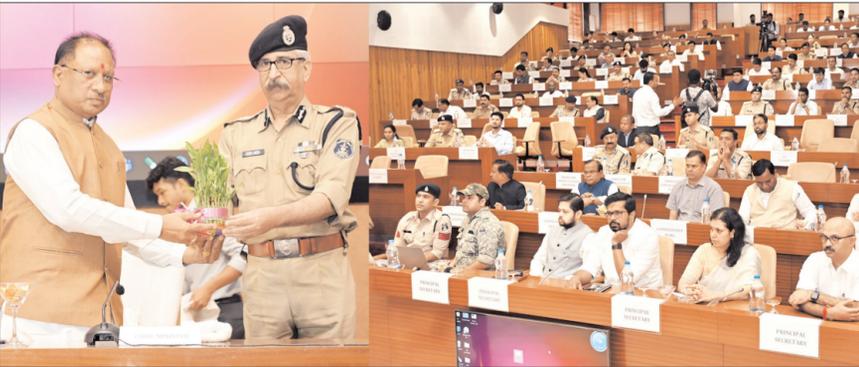
हुल समेत कई नेता नाराज हो गए। सादौरा विधानसभा क्षेत्र में रेणु बाला और पंकी छप्पर ने पार्टी छोड़ दी है।

नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री रामकुमार वाल्मीकि ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी से आए रामकरण काला की उम्मीदवारी के कारण प्रेम हिंगाखेड़ी नाराज हो गए। कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी से हरियाणा महासंग्राम 2024 में इनकार नहीं किया जा सकता। सिरसा से सांसद, बड़ा दलित चेहरा

और कांग्रेस महासचिव शैलजा कुमारी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सियासी टकराव तो खुलकर सामने आ चुका है। शैलजा कुमारी ने सीएम पद की दावेदारी ठोक दी है जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी प्रत्याशी तय करने में अपनी चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होता देख कांग्रेस ने 6 सितंबर 2024 की रात को 32 उम्मीदवारों की दो सूची जारी की है। जिसमें 28 मीजुदा विधायकों पर भी दांव लगाया गया। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में कुमारी शैलजा से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 28 और कुमारी शैलजा गुट के 4 नेताओं को ही टिकट गया

है। कुमारी शैलजा ने न्यूज18 इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि वे अपने घर में तय करें कि मुख्यमंत्री कौन होगा इंटरव्यू में शैलजा ने खुद को सीएम पद की दावेदार बताया। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान शैलजा ने यहाँ तक दिया था कि वे जहाँ भी जाती हैं। कार्यकर्ता उन्हें सीएम कहकर बुलाते हैं।

कांग्रेस की हरियाणा चुनाव में स्थिति भाजपा ने हरियाणा में साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके सरकार बनाई। तो वहीं, कांग्रेस बीते 10 साल से हरियाणा की सत्ता से दूर है। पिछले चुनाव में तो भाजपा ने 40 और कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी। भाजपा ने 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी से गठबंधन करके सरकार बना ली थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहा, मगर बात नहीं बनी। सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कांग्रेस सूची 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस और आम आदमी के बीच गठबंधन हो।



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले। आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे। बेवजह किसी नागरिक को परेशान न किया जाए। पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों के साथ मित्रवत हो। पुलिस थानों का वातावरण ऐसा हो कि आम नागरिक को पुलिस थानों में प्रवेश करते समय सहयोग की उम्मीद हो।

हरियाणा में कमजोर पड़ रही भाजपा, बगावत के सुर से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

हरियाणा में 05 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में मतदान के लिए अब 4 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राज्य की सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियाँ पूरे जोश के साथ चुनावी रण में हैं। वहीं भाजपा भी हरियाणा में अपनी पैठ बनाने की जुगत में जुटी है। लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कमजोर आंका जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। वहीं 5 सीटों कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस राज्य में अति उत्साहित नजर आ रही है।

साथ ही साल 2014 के बाद कांग्रेस पहली बार बीजेपी से मुकाबले के टकराव में दिखी। भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान 40 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं भाजपा के लिए एक चिंता यह भी है कि जाट वोटबैंक लगातार पार्टी के खिलाफ वोट करता आ रहा है, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा धुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जेजेपी और आईएनएलडी जैसे दलों के उतरने से जाट वोटबैंक बट जाएंगे। भले ही जाट वोटबैंक बड़े पैमाने पर एकजुट है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बिमरदा की प्रत्याशी मैदान में उतारने का असर साफ दिखता है। इसलिए भाजपा

को ऐसी कई सीटों पर उम्मीद की किरण दिख रही है। रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अंबाला व कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी आबादी है। प्रास जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी को खुद के बलबूते पर बहुमत मिलने की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है। लेकिन भाजपा के पहले नंबर की पार्टी बनने के अब भी चांस हैं। इसके अलावा राज्य में पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं, जो टिकट न मिलने पर पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में यह इस बात का सबूत है कि राज्य में पार्टी कमजोर पड़ रही है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आने से भाजपा वैसे भी बैकफुट पर थी।

असम में ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े मामलों सीबीआई को

नई दिल्ली। असम में ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी से जुड़े 32 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। असम कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रक्रियाओं के चलते मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने में लगभग एक महीने का समय लगेगा। सीएम ने कहा कि 20 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और महिलाएं इन कंपनियों का प्रचार करते हैं। इन कंपनियों ने लोगों से शेयर बाजार में निवेश करने पर भारी रिटर्न देने का दावा करते हुए करोड़ों रुपये जुटाए। इसके बाद कंपनियाँ निवेशकों का भुगतान नहीं कर सकीं। इन घोटालों में अब तक 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मामलों की जांच के लिए 14 एसआईटी बनाई गई हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सीएमएएए योजना के तहत 25,238 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई। इन लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये मिलेंगे। इसमें एक लाख रुपये सब्सिडी होगी। जबकि एक लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण होगा।

केजरीवाल के बाहर आने से खुश नहीं है कांग्रेस

नई दिल्ली। केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल, यह सिर्फ जमानत है। कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी इसे सिर्फ एक प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानती है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि हम इसे इससे अधिक किसी चीज के रूप में नहीं देखते हैं। अभी तक आरोपों से बरी होने की कोई बात सामने नहीं आई है। अंतिम फैसला अभी भी लंबित है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली सशर्त जमानत के बाद आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

संसदीय समिति लोक उपक्रमों, सौर निगमों की करेगी जांच

नई दिल्ली। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों की जांच करने के लिए अधिकृत संसद की एक समिति बीमा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सौर ऊर्जा निगमों के प्रदर्शन की जांच करेगी। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के प्रदर्शन की जांच भी करेगी। जानकारी के मुताबिक भाजपा सांसद बैजयंत पांडे की अध्यक्षता वाली समिति सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करेगी। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार के जोर के बीच संसदीय समिति सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेबी) का मूल्यांकन करेगी। बता दें कि संसदीय समिति समय-समय पर जांच के लिए ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विषयों का चयन करती है, जिन्हें वह उचित समझती है। वहीं संबंधित मंत्रालय या उपक्रम को सदस्यों की जानकारी के लिए उन विषयों से संबंधित आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद

संजौली। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हथौड़ा लेकर खुद ही मस्जिद तोड़ने की घटना की खबर चर्चा हो रही है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी है। शिमला की सड़कों पर बवाल देख मंडी में रहने वाले मुस्लिम मस्जिदों के अवैध हिस्से को खुद ही तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मस्जिद का ये हिस्सा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाया गया था जिसे तोड़ा जा रहा है। शिमला और मंडी में हिंदुओं का प्रदर्शन देख पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन शांति की बातें करनी शुरू कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने अब खुब संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का प्रस्ताव रख दिया है। मस्जिद के इमाम अब बोल रहे हैं कि अमन और भाई चारा बस बना रहना चाहिए। शिमला के जामा मस्जिद के इमाम मुन्ता मोहम्मद शफ़ी कासमीने कहा कि हमने इसमें (जापन) कहा है कि, इस क्षेत्र में इस सीमावर्ती राज्य में भाईचारे (समुदायों के बीच) की एक बड़ी आवश्यकता है।

चीन सीमा पर बढ़ेगी ताकत, जोरावर टैंक का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षण के दौरान टैंक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेगिस्तानी इलाके में परीक्षण के दौरान जोरावर ने कुशलतापूर्वक सभी लक्ष्य भेद दिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और एलएंडटी डिफेंस 25 टन वजन की टैंक का निर्माण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय हल्के टैंक के सफल परीक्षणों को महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर बताया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में गलवां घाटी में हुई झड़पों के बाद से सेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जोरावर को भी इसलिए तैयार किया गया है। भारतीय सेना जिन सीमा पर 350 से अधिक हल्के टैंकों की तैनाती की तैयारी कर रही है। इनमें से अधिकतर को पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जोरावर टैंक की तुलना इसी श्रेणी में बनाए गए चीन के टैंकों से की जा रही है। जोरावर की तैनाती से चीन सीमा पर तैनात भारतीय लड़ाकों को चपलता, गतिशीलता और परिचालन क्षमता में इजाफा हो जाएगा।

रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को रोकने के लिए भारत-चीन ने कर ली दोस्ती

रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया मिलकर काम करना चाहती है। लेकिन क्या ये रूस के बिना संभव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पक्ष को पूरी दुनिया के सामने रखा। विदेश मंत्री ने कहा कि बिना रूस के इस युद्ध को समाप्त करने का विचार भी करना व्यर्थ है। बिना रूस के बातचीत नहीं हो पाएगी। इसलिए एक बार फिर भारत ने इस बात को जोर देकर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को रोकना जरूरी है और इसके लिए रूस से बातचीत को भी इसका अहम हिस्सा बताया। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत ने इस बार चीन के साथ चर्चा की है। एनएसए अजीत डोभाल सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग का हिस्सा थे। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक

साथ बैठकर आगे की कूटनीति पर चर्चा कर रहे थे। ब्रिक्स देशों की मिलकर की गई इस बैठक में आगे आने वाले संघर्षों और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धताओं को जारी करना था। सबसे जरूरी बात यहां पर ये है कि ब्रिक्स देशों के सदस्यों में चीन और भारत आमने सामने थे और दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हो रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। डोभाल-वांग के बीच हुई बैठक से दोनों पक्षों में हाल के प्रयासों की समीक्षा करने का अवसर मिला। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने तत्परता से काम

करने, शेष क्षेत्रों में पूर्ण वापसी के लिए प्रयास दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और एलएसी का सम्मान किया जाना संबंधों में सामान्य स्थिति के लिए आवश्यक है। दोनों पक्षों को प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत-चीन संबंध न केवल दो देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत दुनिया का सामना करते हुए, चीन और भारत को दो प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए, एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए और उपभोग से बचना चाहिए।

जी 7 में आप जाने नहीं देंगे, इसलिए बनाया खुद का क्लब-जयशंकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर देश के लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया है। उन्होंने पश्चिमी देशों को एक ऐसा जवाब दिया है, जिसकी हर भारतीय आज तारीफ कर रहा है। एस जयशंकर ने स्विजरलैंड के जिनेवा में ग्लोबल सेंट्रल फॉर सिस्कोरिटी पॉलिसी को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल, जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि ब्रिक्स क्यों है और क्या इसका विस्तार होगा? इस सवाल पर एस जयशंकर ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि एक क्लब था, जिसे जी 7 कहा जाता था। जी 7 में आप लोग किसी और देश को प्रवेश करने से रोकते थे। इसलिए हमने अपना खुद का क्लब बनाया। इसके साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि जी 20 के रहते अगर

जी 7 का अस्तित्व रह सकता है तो कोई कारण नहीं है कि ब्रिक्स का अस्तित्व न हो। इसके साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि हमने ब्रिक्स का विस्तार किया है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का क्लब बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब भी इस बात से हैरान हूँ कि जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उत्तर कितना असुरक्षित हो जाता है। जयशंकर ने बताया कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने समय के साथ अपना महत्व प्राप्त किया, क्योंकि अन्य लोगों ने भी इसमें महत्व देखा। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प समूह है, क्योंकि, यदि आप इसे देखें, तो आमतौर पर, किसी भी क्लब या किसी भी समूह का या तो भौगोलिक निकटता या कुछ सामान्य ऐतिहासिक अनुभव होता है, या, आप जानते हैं, बहुत मजबूत आर्थिक संबंध होता है।



कांग्रेस विधायक मंडावी ने भाजपा और पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

सरपंच विजय पाल शाह मंडावी की गिरफ्तारी को लेकर कहा- बेवजह फंसाया गया

बीजापुर। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत तोयनार के सरपंच कांग्रेस कार्यकर्ता विजय पाल शाह मंडावी और एमैया जंगम की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि उन्हें जबरन दबाव डालकर नक्सली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जो कि निंदनीय है।

विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता में घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दिनांक 1 मार्च 2024 को ग्राम तोयनार में एक शादी समारोह में शामिल होने तोयनार क्षेत्र के जनपद सदस्य और भाजपा नेता स्वर्गीय तिरुपति कटला गए हुए थे और उसी दिन शादी समारोह से वापस लौटते समय अचानक नक्सलियों ने उन पर धार धार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तत्काल गांव के सरपंच विजय पाल शाह मंडावी ने वाहन में घायल हुए स्वर्गीय तिरुपति कटला को जिला अस्पताल बीजापुर लाया, जहां उपचार के दौरान उनकी



मौत हो गई थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को संकीर्ण मानसिकता और बदले की राजनीति ने जबरन बिना किसी तथ्य के जिले के एक बड़े पंचायत के सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भाजपा के शासनकाल में अब यह स्थिति निर्मित हो चुकी है कि कोई नेता या जनप्रतिनिधि किसी के शादी समारोह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने जाता है तो उसे संदेह के नजर से देखा जाता है।

जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तोयनार के सरपंच और उसी गांव के एमैया जंगम की गिरफ्तारी है। विधायक विक्रम मंडावी ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रार्थी सुरेश कटला ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिन्हें वह जानता है तो फिर उन्होंने घटना के वक्त तोयनार के सरपंच को क्यों नहीं पहचाना? जबकि वह उस गांव का सरपंच है जिनसे गांव के लोग रोज मिलते हैं।

विधायक विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि भाजपा षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर जेल में डालने का काम कर रही है जो कि निंदनीय है। भाजपा 'फंसाओं और जेल में डालो' की षड्यंत्र वाली नीति अपनाई है। भाजपा सरकार के इस फंसाओं और जेल में डालो की षड्यंत्र वाली नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी डटक मुकाबला करेगी।

पानी से गणपति को बचाने ओढ़ाया छाता

तखतपुर। यूं तो गणपति बप्पा गांव से लेकर हर शहरों तक अलग अलग अंदाज में विराजे हुए हैं, जहां अपने जुदा अंदाज के लिए गणपति बप्पा की चर्चा भी जोरों पर हो रही है। इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लाक के ग्राम लिम्हा के गणेश पंडाल में बारिश का पानी टपकने से गणेशजी की मूर्ति को बचाने उसे छतरी ओढ़ाया गया है।

दरअसल पिछले 3-4 दिनों से बारिश की झड़ी ने हर किसी को परेशान किया है। तखतपुर से बेलपान रोड पर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम लिम्हा का है, जहां गणेश पंडाल भारी बारिश- हवा गुंफान से उखड़कर गिर गया। गणेश जी की मूर्ति को पानी की बोझार ना भिगो सके इसलिए उनके हाथों में छतरी पकड़कर ओढ़ाया गया है, जिसे दिखने गांवभर के लोग पहुंच रहे हैं। वहीं बारिश के कम होने पर गणेश उत्सव समिति के बच्चे पंडाल को ठीक करने में लगे हैं।

90 हितग्राहियों को नहीं मिला जुलाई का चावल लेकिन कार्ड में हुई इंटी

जौली गांव में सरकारी राशन का संकट

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जौली में सरकारी राशन न मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के 380 राशन कार्डधारी परिवारों में से 90 हितग्राही पिछले दो महीनों से चावल के लिए तरस रहे हैं। जिससे उन्हें बाहर से चावल खरीदना पड़ रहा है। गुरुवार को ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपना विरोध जताया।

पीडीएस दुकान में चावल लेने आई ग्रामीण महिला गीत ने बताया कि चावल लेने आने पर राशन दुकान संचालक धमकी देने लगता है। कहते हैं चावल नहीं देंगे। जहां शिकायत करनी है कर लो कहते हैं। जुलाई का चावल रुका है। इसी तरह कई और ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की।

ग्रामीण आनंद प्रसाद यादव ने कहा समूह वाले कभी बोलते हैं कि चावल नहीं आया, कभी चना या कभी शक्कर नहीं आने की बात करते हैं। सही समय पर राशन नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है कि समूह से सुसाइटी हटाकर ग्राम पंचायत को हेंडओवर किया जाए।

ग्रामीण राम सिंह ने कहा राशन नहीं मिल रहा है। सुसाइटी समूह से हटाने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। ग्रामीण राकेश प्रसाद यादव ने कहा जुलाई का चावल भी नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि



अगले महीने मिलेगा।

राशन बांटने वाले सेल्समैन कृपाल राम ने बताया कि जून के महीने में चावल पूरा नहीं आ पाया था इसलिए जुलाई का चावल नहीं दे पाए। राशन कार्ड में इंटी किए थे लेकिन बाद में चावल कम हो गया। सेल्समैन का कहना है कि कार्ड में इंटी पहले हो गई थी। साथ ही वे भी बताया कि हर महीने 120 क्विंटल चावल आता है। लेकिन इस बार 81 क्विंटल चावल आया, बाकी का चावल नहीं आया।

एसडीएम प्रवीण भगत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, जौली ग्राम पंचायत में 90 हितग्राहियों को जुलाई महीने का चावल नहीं मिला है, जबकि इसकी इंटी राशन कार्ड में कर दी गई है। खाद्य निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करें। जांच में शिकायत सही मिलने पर पीडीएस दुकान वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी।

वन परिक्षेत्र भानपुरी के अतिक्रमण को अभियान चलाकर किया जा रहा वन भूमि को मुक्त

जगदलपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर वन भूमि को मुक्त किया जा रहा है। निर्देशानुसार वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक श्री आर.सी.दुर्गा के मार्गदर्शन एवं वनमण्डलाधिकारी बस्तर श्री उत्तम गुप्ता के निर्देशन में उडनदस्ता, समस्त स्टॉफ ने वन परिक्षेत्र भानपुरी के अन्तर्गत अतिक्रमण की शिकायत के जाँच के लिए राज्य स्तरीय उडनदस्ता टीम एवं वृत्त स्तरीय उडनदस्ता टीम के द्वारा कार्यवाही किया गया।



राज्य स्तरीय उडन दस्ता टीम रायपुर के द्वारा चपका पी.एफ. 1077 नया 86 में तीन व्यक्तिओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनके को गई कार्यवाही के तहत उनके पास से 8 बंडल 110 र.मी. चैन लिंक एवं 73 नग बांस के फेंसिंग खुंटा जप्त किया गया। जिसमें ग्राम सोनारपाल से श्री विकास देवांगन द्वारा 0.226 हेक्टेयर में मिर्ची की खड़ी फसल जप्त कर उनके

विरुद्ध वन अपराध कायम किया गया। ग्राम छेडीपारा सोनारपाल से श्री राजू द्वारा 0.450 हेक्टेयर में धान की खड़ी फसल जप्त कर और ग्राम-चपका की श्री तुलसी 0.050 हे. धान की खड़ी फसल जप्त कर उनके विरुद्ध वन अपराध कायम किया गया। इसी तरह वृत्त स्तरीय उडन दस्ता टीम जगदलपुर के द्वारा ग्राम मुरकुची नया 64 में 20 अतिक्रमकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 9.791 हेक्टेयर रकबा में मक्का एवं उड़द के खड़ी फसल जप्त किया गया है। उनके 10 बंडल फेंसिंग तार एवं 300 नग फेंसिंग खुंटा मौके से जप्त किया

गया। जिसमें ग्राम-मुरकुची से श्री डमरू द्वारा 0.733 हेक्टेयर. मक्का खड़ी फसल, श्री फूलसिंग द्वारा 2.211 हेक्टेयर. बारवेड वायर 45 कि.ग्रा., फेंसिंग 3 क्विंटल., खड़ी फसल मक्का, उड़द जप्त कर, श्री सुरेश द्वारा 2.753 हे. बारवेड वायर 60 कि.ग्रा., मिश्रित फेंसिंग 4.50 कि.ग्रा., खड़ी फसल मक्का, श्री के.लूराम एवं अन्य 05 व्यक्ति 2.622 हेक्टेयर, बारवेड वायर 70 कि.ग्रा. मिश्रित जलाऊ 4 क्विंटल, खड़ी फसल मक्का जप्त कर, श्री रूपनाथ अन्य 03 व्यक्ति .572 हेक्टेयर बारवेड वायर 25 कि.ग्रा. मिश्रित जलाऊ फेंसिंग 2 क्विंटल, खड़ी फसल मक्का, उड़द जप्त कर उनके विरुद्ध वन अपराध कायम किया गया। समस्त प्रकरणों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर में प्रस्तुत किया जाएगा।

बारहमासी सब्जी के व्यापारी बने राजकुमार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया कदम

एमसीबी। राजकुमार पिता अमीरसाय ग्राम पंचायत बरदर के निवासी हैं, कृषक राजकुमार का जीवोपार्जन का माध्यम कृषि पर आधारित था। राजकुमार पेशे से लघु कृषक है, वह वर्षा की पानी के भरोसे धान की खेती करता था, परन्तु कुछ वर्षों से बारिश की अनियमितता होने के कारण कृषि कार्य हेतु सिंचाई सुविधा ना होने के कारण दूर से पानी लाना पड़ता था। जिससे उसे अधिक परिश्रम एवं अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था और उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम होता था एवं वर्ष में केवल एक ही फसल (खरीफ) ले पाता था। राजकुमार अन्य ग्रामीण कृषकों की तरह खेती के लिए वर्षा के जल पर ही निर्भर था और वर्षा पर्याप्त नहीं होने पर परिवार को गांव के ही अन्य जगह में मजदूरी करनी पड़ती थी। हमेशा से ही उसके स्वयं के खेत में सिंचाई सुविधा की कमी होती थी और वह हमेशा से चाहते थे की उनके खेत या खेत के आसपास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाये। जिससे अल्पवर्षा के समय कृषि हेतु सिंचाई सुविधा मिल सके तथा पैदावार अधिक हो सके।

राजकुमार ने इस सपना को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत निजी डबरी निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में अर्जी दी। इसके लिए ग्राम पंचायत में



एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। डबरी निर्माण के पश्चात् इस बरसात में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता होने से अब रामकुमार खुशहाल किसान कहलाने लगे हैं। रामकुमार बताते हैं कि खेत में निजी डबरी निर्माण होने के पश्चात खरीफ सीजन में धान फसल की बहुत अच्छी पैदावार होने लगी है। राजकुमार और उनके परिवार ने इस डबरी का उपयोग बारहमासी सब्जी उत्पादन में भी किया करते हैं, जिसमें सरसों, तिखी, भुट्टा (मक्का) से लेकर धान की फसल और मछली पालन तक का सफर तय किया गया है। इस उपलब्धि ने उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। पूरे परिवार ने एकजुट होकर खेती-बाड़ी का कार्य किया और विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया, जिससे उन्हें एक स्थायी आय का स्रोत प्राप्त हुआ। राजकुमार का कहना है कि वह अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसी दिशा में लगातार प्रयासरत हैं।

भारी हंगामे के बाद स्थगित हुई सामान्य सभा

कांग्रेस पार्टी का अनोखा अंदाज, कचरे को बनाया ड्रेस

जगदलपुर। जगदलपुर में शुक्रवार को सुबह नगर निगम कार्यालय में सामान्य सभा आयोजित किया गया, इस सामान्य सभा को लेकर पहले से ही विपक्ष दल ने अपनी रणनीति तैयार करके रखे हुए थे, जिसके चलते जैसे ही सामान्य सभा शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा कचरे को अपना ड्रेस बनाकर सभा में पहुंचे जहाँ हंगामे के बीच दोनों पक्षों को समझाया गया, लेकिन बात नहीं मानने पर 1 घंटे के लिए सभा को स्थगित करना पड़ा।

बताया जा रहा है कि नगर निगम की सामान्य सभा में कांग्रेस पार्टी राजेश राय के द्वारा कचरा बनकर सामान्य सभा में पहुंचे, जहाँ उन्होंने शहर में कचरा डीपिंग यार्ड नहीं होने के कारण शहर में जगह जगह कचरा फेंके जाने की बात कहते हुए कहा कि वार्डों में भी नियमित रूप से सफाई नहीं होने के कारण आमजन कचरा को कहीं भी फेंक रहे हैं, साथ ही कचरा वाहन भी समय पर वार्डों



में नहीं आने के कारण जगह जगह लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है।

लगातार चले हंगामे के बीच महापौर सफिरा साहू ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को सामान्य सभा से बाहर निकालने के साथ ही कपड़ा बदलकर आने की बात कही, सामान्य सभा के इस सदन के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाया, इस दौरान दलों के द्वारा गर्भगृह तक पहुंच गए, अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके चलते अध्यक्ष ने 1 घंटे के लिए सभा को स्थगित कर दिया है।

आधा दर्जन वरिष्ठ स्टॉफ नर्सों का तबादला

राजनांदगांव। जिला चिकित्सालय से राज्य शासन ने आधा दर्जन वरिष्ठ स्टॉफ नर्सों को जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ कर दिया है। जिला चिकित्सालय में पहले से ही वार्डों में स्टॉफ नर्सों की काफी कमी रही है और उनके तबादले से स्टॉफ और कमी हो जाएगी लेकिन राज्य सरकार ने स्थानांतरित स्टॉफ नर्सों की जगह नई पोस्टिंग करना भूल गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला चिकित्सालय में कार्यरत स्टॉफ नर्सों को चिकित्सा शिक्षा विभाग (डीएमई) के मूल स्टॉफ नर्स जीत वार्डेंकर को सिविल अस्पताल खैरागढ़ से भीमव अवम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर, शकुन वर्मा को जिला चिकित्सालय राजनांदगांव से जगदलपुर, रीना अनिल को जिला चिकित्सालय राजनांदगांव से जगदलपुर, रबीला भीमटे को जिला चिकित्सालय राजनांदगांव से रायपुर, भुनेश्वरी साहू को जिला चिकित्सालय राजनांदगांव से रायपुर, स्वाति सिमनकर को जिला चिकित्सालय राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर स्थानांतरण किया गया है।

जगदलपुर में डायरिया की दस्तक, जांच में जुटी टीमें

जगदलपुर। जगदलपुर दरभा ब्लाक का कोएनार गांव। यहां अचानक हुयी दो मौतों ने स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय कर दिया है। गांव में डायरिया का प्रकोप देखा गया, जानकारी के अनुसार डायरिया के चलते यहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग रामसिंह की मौत हो गई, एक 9 वर्षीय बच्चा भी अचानक स्कूल में बेहोश हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया। एक गांव के दो लोगों की मौत की जानकारी मिलते ही दरभा बीएमओ पीएल मंडावी की 10 सदस्यीय टीम तत्काल प्रभाव से कोएनार पहुंची जहां की तस्वीर इन्हें भयावह दिखी। गुरुवार के दिन गांव के करीब 50 से 60 ग्रामीण अपना इलाज करने के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचे थे और सभी को लगभग एक ही प्रकार की समस्या थी। इलाज के लिए आए सभी मरीजों का बीपी, शुगर, मलेरिया व अन्य जांच शुरू कर दी गयी है और लोगों की देखरेख के लिए कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई है। बीमारी का सच जान रहे स्वास्थ्य प्रहरीयों ने गांव में लगे हैंडपंप के पानी का सैंपल भी लिया है।

शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा पुल के बराबर तक पहुंचा पानी

भाटापारा। बलोदा बाजार जिले के करही थाना क्षेत्र स्थित अमलदीहा घाट पर शिवनाथ नदी का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। हाल ही में हुई मूसलधार बारिश के कारण नदी में पानी का स्तर बढ़ने से नदी का पानी पुल के बराबर तक पहुंच गया है। पिछले मंगलवार की रात भारी बारिश के चलते विभिन्न जलाशयों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, और इन जलाशयों से निकाले गए पानी को शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बलोदा बाजार जिले के शिवनाथ नदी किनारे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन और पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और नदी किनारे के गांवों को सतर्क कर दिया गया है। यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने-जाने की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

भोरमदेव अभ्यारण्य में एक साथ पहुंचे बाघ-बाघिन

कवर्धा। कबीरधाम जिले के भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में लंबे समय बाद बाघ बाघिन की चहलकदमी हुई है। पिछले एक महीने से बाघ के दहाड़ के साथ वन विभाग के कैमरे में इसकी तस्वीर भी नजर आई है। खास बात ये है कि इस बार बाघ बाघिन जोड़े में भोरमदेव पहुंचा है। वन विभाग ने भोरमदेव वाइल्ड वाइल्डलाइफ सेंक्यूरी लगे लगभग 25 गांवों में बाघ बाघिन की मौजूदगी और जंगल में नहीं जाने की मुनादी कराई है। भोरमदेव अभ्यारण्य में पिछले एक महीने से बाघ और बाघिन की चहलकदमी हो रही है। इसके लिए विभाग ने जगह-जगह ट्रैप कैमरा लगाया हुआ है। जिससे बाघ के जंगल में घूमने की कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। कई जगहों पर बाघ के फूट प्रिंट भी मिले हैं। लगातार वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी बाघ के मूवमेंट पर नजारा बनाए हुए हैं। वनमंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि भोरमदेव अभ्यारण्य के कोर रेंज में बाघ बाघिन का मूवमेंट की सूचना मिली है। जंगल के आसपास 24 से 25 गांव हैं जहां बाघ के विचरण को लेकर मुनादी करा दी गई है।

टीचर की मांग को लेकर पालकों ने स्कूल में जड़ा ताला

महासमुंद। पालक और बच्चों ने महासमुंद के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में ताला लगा दिया है। इस स्कूल में सिर्फ एक की शिक्षक हैं, जो 3 क्लास के 71 बच्चों पढ़ाते हैं। यही कारण है कि पालक और बच्चों ने शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल में ताला लगा दिया है। बता दें कि स्कूल में कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक के 71 बच्चे हैं, जो एक प्रधानपाठक व एक शिक्षक के साथ हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिसोधा के एक शिक्षिका को 2018 से अटैचमेंट में बृजराज पाठशाला महासमुंद में अटैच कर दिया है और उनको सेलरी सिसोधा स्कूल से दिया जाता है। वहीं, नियमानुसार एक स्कूल में एक प्रधानपाठक और तीन शिक्षक होने ही चाहिए। लेकिन यहां एक ही शिक्षक हैं। जिसको देखते हुए पालकों और बच्चे शिक्षक की मांग को लेकर स्कूल में ताला लगाया है। शिक्षा विभाग अब दूसरे शिक्षक को अटैच करने की बात कह रहे हैं, पर पालक मानने को तैयार नहीं हैं।

महासमुंद रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस

महासमुंद। महासमुंद से रायपुर-दुर्गा की ओर और महासमुंद से विशाखापट्टनम की ओर जाने वाले यात्रियों को अब वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन आज अचानक महासमुंद रेलवे स्टेशन पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देखकर यात्री काफी खुश हुए। क्योंकि यह इस रूट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है।



शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत का उद्घाटन पहले 15 सितंबर को होने वाला था, जिसके स्थान पर समय में बदलाव कर अब 16 सितंबर को इसका शुभारंभ होगा। 16 सितंबर की शाम 4:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वचुअली झंडा दिखाकर रायपुर से रवाना करेंगे और यह शाम 4:45 बजे महासमुंद पहुंचेगी। महासमुंद में इसका 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। यह शाम 4:50 मिनट पर महासमुंद से रवाना हो जायेगी। यह ट्रेन रात 12:20 में विशाखापट्टनम पहुंचेगी।

वजन तिहार शुरू, हर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों से मिलेगा कुपोषण का डाटा

रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश के कई जिलों ने वजन तिहार 2024 की शुरुआत की है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 12 ले 23 सितंबर तक वजन तिहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश के हर एक आंगनबाड़ी केन्द्र में ये तिहार मनाया जा रहा है। इस वजन तिहार के जरिए 0 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्तर का आकलन किया जाता है।



कोरबा में वजन तिहार- कोरबा जिले के 2598 आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन तिहार का आयोजन किया गया। इसमें 0 से 6 साल के सभी बच्चों के वजन और ऊंचाई की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में 12 से 23 सितंबर तक वजन तिहार मनाया जाएगा। कोरबा में पोषण अभियान अन्तर्गत 'राष्ट्रीय पोषण माह 2024' का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा अंतर्गत वजन तिहार की शुरुआत

नापजोख के दौरान उत्साहित नजर आए। इस बीच कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मनाए जाने वाले वजन तिहार के लिए जिले के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया।

सूरजपुर में वजन तिहार- सूरजपुर जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत वजन तिहार का शुभारंभ किया गया। जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में इसकी शुरुआत की गई। इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन और ऊंचाई जांच कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की स्थिति का पता लगाया जा रहा है। इस दौरान उनके कुपोषण के स्तर की भी जांच की गई।

दंतेवाड़ा में वजन तिहार- दंतेवाड़ा के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार वजन तिहार की शुरुआत की गई। इस दौरान कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में 12

सितम्बर से 23 सितम्बर तक आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन तिहार किया जाएगा। साथ ही 6 साल तक के बच्चों का वजन निर्धारित तिथि तक कलस्टरवार तिथि का निर्धारण करते हुए कलस्टर के चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों का वजन लिया जाएगा, ताकि प्रत्येक कलस्टर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपरवाइजर्स की उपस्थिति में बच्चों का शत प्रतिशत और सही-सही वजन लिया जाना सुनिश्चित हो सके।

खैरागढ़ में वजन तिहार- खैरागढ़ में वजन तिहार की शुरुआत हो चुकी है। यहां जिला कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार 12 सितंबर से 23 सितंबर 2024 तक वजन तिहार का आयोजन किया जाएगा। बच्चों में स्तर के अनुसार उनका वजन लेने पर पोषण स्तर की जानकारी ली जाएगी। साथ ही पूरे राज्य में कुपोषण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 15 को

आएंगे छत्तीसगढ़

रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। दो दिनों के प्रवास के दौरान पायलट वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। जानकारी के अनुसार, पायलट के साथ दोनों नवनियुक्त प्रभारी सचिव एसए संपत कुमार और जरिता लैतफलांग भी छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रवास के दौरान नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।

सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर के साथ 50 से ज्यादा संपत्ति ईडी ने की अटैच

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहें सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच कर दिया है। ईडी ने अटैच की गई संपत्तियों का बोर्ड उनके घर में चप्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि अटैच की गई संपत्तियों में सौम्या चौरसिया का भिलाई स्थित सूर्य विहार स्थित निवास भी शामिल है। सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

बलौदाबाजार आगजनी में सेंट्रल जेल में कैद नेताओं से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता

बिलासपुर। बलौदाबाजार आगजनी मामले में बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने कांग्रेस जांच समिति के सदस्य पहुंचे। मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेताओं पर जेल के भीतर दबाव बनाया जा रहा है। रासुका लगाने और परिजनों को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। कोरे कागज में दस्तखत कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार में भाजपा नेताओं ने घटना कराई है। बलौदाबाजार आगजनी मामले में बिलासपुर सेंट्रल जेल में 25 से अधिक कांग्रेस नेता कैद हैं। इनसे मुलाकात करने के लिए केंद्रीय जेल पहुंचे नेताओं में पूर्व मंत्री धनंजय साहू, पूर्व डी। मंत्री शिव डहरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. प्रेमचंद जायसि, प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवा देवांगन, शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी और पूर्व विधायक शैलेश पांडेय शामिल थे।

महादेव सट्टा एप मामले: हाई कोर्ट में ईडी ने रखा अपना पक्ष, 19 को अगली सुनवाई

बिलासपुर। महादेव सट्टा एप से जुड़े मामले में शुक्रवार को बि ल ल स पुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने आज फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर निर्धारित की है। इस दिन बचाव पक्ष अपना प्रतिउत्तर पेश करेगा। बता दें, मामले में विशेष अदालत की तरफ से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के खिलाफ महादेव सट्टा एप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उपपल ने याचिका दायर की है। बचाव पक्ष के याचिका पर आज हाईकोर्ट ने ईडी का पक्ष जाना है, हालांकि बचाव पक्ष की दलीलों 19 सितंबर को सुनी जाएंगी।

कह- जब सलिपता नहीं तो क्यों जाना पड़ा जेल

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोयला लेवी मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने जेल पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि सब कुछ बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं। कांग्रेस की सरकार में सिंडिकेट का जन्म हुआ था। जब सल्लिसता नहीं है तो ऐसी कौन सी बात है जो जेल में जाना पड़ गया। किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी। जिनकी जमानत नहीं हो रही है, वे सभी लोग जेल में हैं। अत्याचार आपकी सरकार में हुआ है, भ्रष्टाचार आप करें, आपके लोग करें। कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। टारगेट करने की बात बहुत हास्यास्पद है। जनता सब समझती है इसलिए पांच सालों में ही सरकार चली गई।

अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित मिले न्याय : साय

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले। आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे। बेवजह किसी नागरिक को परेशान न किया जाए। पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों के साथ मित्रवत हो। पुलिस थानों का वातावरण ऐसा हो कि आम नागरिक को पुलिस थानों में प्रवेश करते समय सहयोग की उम्मीद हो। वे आज राजधानी के न्यू-सर्किट हाउस में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं एसपी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दंड संहिता को बदल कर न्याय संहिता कर दिया है। इसका जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पुलिस को इन नए कानूनों के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वयं को ढालना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और पिछले वर्षों की तुलना में अपराध की संख्या में कमी आई है। राज्य में नए सिरे से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत - मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए सिरे से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, इससे अपराधों को रोकने



में मदद मिलेगी। लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि पुलिस उनके साथ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में गौ-तस्करी व नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कड़ाई से नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री, जुआ, सट्टा एवं गांजा की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाकर दोषियों पर विधिस्मृत कार्यवाही सुनिश्चित करें। समाज में अशांति फैलाने वालों, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें और उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए तथा ऐसे केस में प्राथमिकता से त्वरित गति से

कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बंदर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई रकनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बंदर की कार्रवाई केवल कागजों पर ना हो बल्कि वास्तव में हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब बिक्री की बहुत शिकायत है, जिसमें पुलिस पर संरक्षण के आरोप लगते हैं, यह बिलकुल नहीं होना चाहिए। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह बंद होना चाहिए। कई जगहों में अवैध शराब बिक्री की जांच को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, इस संबंध में शिकायतें मिलती हैं कि जांच टीम सही से जांच नहीं कर रही, अधिकारी जांच में उपस्थित नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर पुलिस रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होते हुए पुलिस की

सक्रियता का स्तर और बेहतर करने की जरूरत है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि दुर्ग पुलिस रेंज को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये उचित नहीं है। कई मामलों में आरोपी फरार हैं, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजनांदगांव पुलिस रेंज में कुछ जगह अच्छे काम हुए हैं, त्रिनेत्र एप और चिटफंड मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सीट-बेल्ट, हेलमेट पहनने की समझाइश दी जाए। उन्होंने बैठक में आने वाले दिनों में पुलिसिंग को और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने की दिशा में किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर रेंज की समीक्षा करते हुए राजधानी में पुलिसिंग की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रायपुर प्रदेश की राजधानी है और यहां की पुलिसिंग का सर्वोत्तम स्तर पर होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में भूमाफियाओं द्वारा शासकीय और आम नागरिकों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों

पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर इस समस्या पर कड़ी नजर रखें और तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीली दवाइयों की बिक्री पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस अवैध व्यापार के इकोसिस्टम को तोड़ना होगा और अपराध की जड़ तक पहुंचकर इसे समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि रायपुर में स्कूल और कॉलेजों में नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं को इस घातक प्रवृत्ति से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने राजधानी में रात की गश्त को और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए पुलिस पेट्रोलिंग को लगातार जारी रखने और संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कहा कि वे योजना बनाकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाएं ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, राज्य के संभागा्युक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी पदयात्रा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। कांग्रेस ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में पदयात्रा करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने बताया कि वे प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, महिला सुरक्षा के मुद्दे और सरकार की विफलताओं को लेकर पूरे प्रदेश में अलग-अलग चरणों में पदयात्रा करेंगे। पहले चरण की पदयात्रा निकाय और पंचायत चुनाव से पहले की जाएगी।

बता दें, यह कांग्रेस की पदयात्रा राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बज्र नेताओं की मौजूदगी में शुरू होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज 125 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे और विभिन्न स्थानों में सभाओं को संबोधित करेंगे। पदयात्रा की तारीखें- 27 सितंबर



को रायपुर से प्रारंभ होगी पदयात्रा। 2 अक्टूबर को गिरौदपुरी में होगा पदयात्रा का समापन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर भी नगरीय निकाय चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शुरू होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज 125 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे और विभिन्न स्थानों में सभाओं को संबोधित करेंगे। पदयात्रा की तारीखें- 27 सितंबर

सवाल उठायी है। बैज ने कहा कि सरकार में समन्वय नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री की दिशा अलग, गृहमंत्री की अलग नजर आ रही है। बैज ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। हत्या और लूट जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। दक्षिण विधानसभा की तैयारी पर सदस्यों के सुझाव सुने गए हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी सदस्यों का बुलावा लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने संगठन के कार्यों पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है।

राजभवन के निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के राज्यपाल ने दिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल श्री रमन डेका ने आज राजभवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बैठक लेकर नया रायपुर में निर्माणधीन राजभवन और वर्तमान राजभवन के निर्माण एवं सुधार कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने नये राजभवन के चल रहे कार्यों के प्रगति की विस्तृत जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वृक्षारोपण कर परिसर को हरा-भरा करने को निर्देश दिये। नए राजभवन में रेनवाटर हावर्डिंग तथा सोलर पैनलों की व्यवस्था करने को कहा। स्टाफ के लिए जो 24 घंटे पालियों में ड्यूटी करते हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को अपने घरों, आस-पास एवं कार्यालय को हरा-भरा करने के लिए पेड़ लगाने को कहा। वर्तमान राजभवन में आवासीय क्षेत्र में चल रहे सुधार जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता श्री



ज्ञानेश्वर कश्यप, विभाग के अधिकारी तथा आर्किटेक्ट उपस्थित थे।

सैनिक कल्याण की योजनाओं का करें बेहतर क्रियान्वयन : डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमन डेका ने सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से शहीदों के परिजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने को निर्देश दिये हैं। राजभवन में आज राज्यपाल श्री रमन डेका ने छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड के गतिविधियों की जानकारी ली।

उप मुख्यमंत्री साव ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय का किया भ्रमण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अमेरिका के अपने अध्ययन प्रवास के दौरान गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा कक्ष, सुरक्षा समिति कक्ष इत्यादि जगहों का भ्रमण कर संघ की कार्यप्रणाली को समझा। अध्ययन दौरे पर साथ गए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रोत सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे। श्री साव संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मुख्य वित्त अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय के आमंत्रण पर (तख्तपुर) के निवासी हैं। श्री साव ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के भ्रमण के बाद कहा कि दुनिया के इतने महत्वपूर्ण कार्यालय में बिलासपुर के राजनांदगांव का बेटा मुख्य वित्त अधिकारी के गरिमामय पद पर



कार्यरत हैं। यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उप मुख्यमंत्री श्री साव न्यूयॉर्क के रॉयल एल्बर्ट्स पैलेस में भारतीय मूल के लोगों द्वारा अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ और देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन, पौराणिक मान्यताओं, संसाधनों और यहां के सीधे-सरल लोगों के बारे में बताया। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ के बारे में अपने विचार भी रखे। श्री साव ने अमेरिका में बसे भारतीयों को छत्तीसगढ़ आने और यहां की अनुभूति व प्राकृतिक सुंदरता को देखने आमंत्रित किया।

33 उप पंजीयक अधिकारियों का हुआ तबादला

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वरिष्ठ उपपंजीयक एवं उपपंजीयक संवर्ग के 33 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी है। इन अधिकारियों को तीन दिन भीतर कार्यभार सम्हालने का निर्देश वाणिज्यिक कर (पंजीयक) विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। जारी आदेश के मुताबिक श्री अमित कुमार शुक्ला वरिष्ठ उप पंजीयक, रायपुर से उप पंजीयक कार्यालय बेरला जिला बेमेतरा, आकाश देवांगन उप पंजीयक, रायपुर से उप पंजीयक कार्यालय डौण्डी लोहारा जिला-बालोद, बृजेश शुक्ला उप पंजीयक, रायपुर से उप पंजीयक कार्यालय गरियाबंद, दिग्विजय चुरेन्द्र वरिष्ठ उप पंजीयक, अभनपुर से उप पंजीयक कार्यालय राजनांदगांव, देवराज साव वरिष्ठ उप पंजीयक, दुर्ग से उप पंजीयक कार्यालय रायपुर, मुकेश अजापाल वरिष्ठ उप पंजीयक, दुर्ग से उप पंजीयक कार्यालय जगदलपुर, श्रीमती दीपाली राजपूत उप पंजीयक, दुर्ग से उप पंजीयक कार्यालय पामागढ़ जिला-जांजगीर-चांपा, बलदेव सिंह पिस्टा (प्रीतम), वरिष्ठ उप पंजीयक, राजनांदगांव से उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग, श्रीमती मागीट टोप्यो वरिष्ठ उप पंजीयक, राजनांदगांव से उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग, श्रीमती पुष्पा मैत्री उप पंजीयक, डोंगरांव से

उप पंजीयक कार्यालय रायपुर, श्रीमती डॉ. लक्ष्मी पाण्डेय वरिष्ठ उप पंजीयक, बिलासपुर से उप पंजीयक कार्यालय रायपुर, पेंडारोड जिला-गोरेला-पेंडा मरवाही, शांतिनूतन कुजूर उप पंजीयक, बिलासपुर से उप पंजीयक कार्यालय सक्की, श्री शशांक गोयल उप पंजीयक, बिलासपुर से उप पंजीयक कार्यालय रायपुर, वरापति सिंह वरिष्ठ उप पंजीयक, महासमुंद से उपपंजीयक कार्यालय रायपुर, श्री विजय कुमार भूले वरिष्ठ उप पंजीयक, गुंडरदेही से उप पंजीयक कार्यालय राजनांदगांव, दिनेश कुमार रड़के उप पंजीयक, डौण्डी लोहारा से उप पंजीयक कार्यालय खैरागढ़, सिद्धार्थ शंकर मिश्रा उप पंजीयक, अंबिकापुर से उप पंजीयक कार्यालय नवागढ़ जिला-बेमेतरा, अजयेश कुमार विश्वकर्मा उप पंजीयक, हरदी बाजार से उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी, बनवाली कश्यप उप पंजीयक, कुनकुरी से उप पंजीयक कार्यालय हरदी बाजार जिला-कोरबा, प्रतीक खेमूका उप पंजीयक, सक्की से उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर, नौगढ़ पटेल उप पंजीयक, पेंडारोड से उप पंजीयक कार्यालय

बिलासपुर, सूर्यकांत भंडारी उप पंजीयक, गरियाबंद से उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर, विनोद कुमार भतरिमा उप पंजीयक, कांकेर से उप पंजीयक कार्यालय अभनपुर जिला-रायपुर, श्रीमती भारती शर्मा वरिष्ठ उप पंजीयक, बेरला से उप पंजीयक कार्यालय रायपुर, एम. आर. ध्रुव (मालिक राम ध्रुव) वरिष्ठ उप पंजीयक, सारंगढ़ से उप पंजीयक कार्यालय धमतरी, उत्तम कुमार टंडन उप पंजीयक, बिलासपुर से उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद, तनोज कुमार भूआर्य से उपपंजीयक कार्यालय पलारी से उप पंजीयक कार्यालय रायगढ़, अलबर्ट कुजूर उप पंजीयक, नयागढ़ जिला बेमेतरा से उप पंजीयक कार्यालय अंबिकापुर, राम कुमार बिलाहरे उप पंजीयक, राजनांदगांव से उप पंजीयक कार्यालय कांकेर, संतराम चौहान उप पंजीयक, चांपा से उप पंजीयक कार्यालय सारंगढ़, वीरेंद्र कुमार श्रीवास वरिष्ठ उप पंजीयक, रायपुर से उप पंजीयक कार्यालय पाटन, उत्तम सिंह राठौर उप पंजीयक, पामागढ़ से उप पंजीयक कार्यालय दंतेवाड़ा तथा भूपेन्द्र कुरे उप पंजीयक, जगदलपुर से उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। इन स्थानांतरित अधिकारियों को तीन दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त होगा सुनिश्चित करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यमुक्त माना जावेगा।

भूपेश बघेल के सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने जेल जाने पर किरण सिंहदेव ने कसा तंज

कह- जब सलिपता नहीं तो क्यों जाना पड़ा जेल

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोयला लेवी मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने जेल पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि सब कुछ बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं। कांग्रेस की सरकार में सिंडिकेट का जन्म हुआ था। जब सल्लिसता नहीं है तो ऐसी कौन सी बात है जो जेल में जाना पड़ गया। किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी। जिनकी जमानत नहीं हो रही है, वे सभी लोग जेल में हैं। अत्याचार आपकी सरकार में हुआ है, भ्रष्टाचार आप करें, आपके लोग करें। कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। टारगेट करने की बात बहुत हास्यास्पद है। जनता सब समझती है इसलिए पांच सालों में ही सरकार चली गई।



कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे के संगठन में टिप्पणी वही करता है, जो फुर्सत में रहते हैं। उनके दौरे का फर्क पहले भी नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 15 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनेदन करते हैं। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से कार्यक्रम में शामिल होंगे। 8 लाख 43 हजार पीएम आवास मिलेगा। पीएम आवास के हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही सिंहदेव ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बताया कि बहुत तेजी से सदस्य बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 लाख से अधिक सदस्य बन गए हैं। सदस्यता अभियान लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। बस्तर संभाग की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी का संस्कार है, आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना: तोखन साहू

खड़ा होना। कांग्रेस का कोई भी नेता हो उनकी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ सरकार के केंजा नक्सली मनवा माटा अभियान पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सात राज्यों को लेकर मीटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है। आने वाले 2 साल के भीतर हमारा छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त हो। नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए, सरकार को यही मंशा है, इसलिए अलग-अलग कदम उठाए जा रहे हैं। ई बस को लेकर बड़ी सौगात पर तोखन साहू ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बड़ी चुनौती है। बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए फंड भी जारी कर लिए हैं। इसका लाभ भी आम जनता को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के फ्लॉइडोवर की सहमति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत सारे निर्माण कार्य होने हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। हर सेक्टर में काम के लिए नीव रखी जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, कार्यालय मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्चरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>

(चतुर्थ आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 158336/निविदा सूचना क्र. 03/वलेलि/2024-25, छुईखदान दिनांक 11.09.2024

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 30.09.2024 17:30 तक ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

कार्य का नाम- खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड छुईखदान को बरैयापाट व्यापकतन योजना के दरबानोला मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से 2400 मी., बरैयापाट माईन आर.डी. 0 मी. से 1800 मी. तक जीवोद्धार एवं सी.सी. लॉन्गिन कार्य तथा 08 ना की.आर.बी., 10 ना फाल, 01 ना माईनर हेड, पक्के कार्य का निर्माण कार्य एवं कोलाबा पार्षद फिनिशिंग का कार्य।

अनुमति लागत- रु. 214.77 लाख

(दिनांक 01.10.2020 के एस.ओ.आर. तथा संशोधित 22.08.2022 के अनुसार)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्चरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 18.09.2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्चरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कानान अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता

जल संसाधन संभाग, छुईखदान

कृते मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर, छ.ग.

जी-242502462/8

राहुल गांधी और जुबानी सियासत का गणित

अजय बोकिल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रायोजित अमेरिका दौरा हंगामे का कारण बनेगा, इसका अंदाजा तो पहले ही से था। इसका एक कारण यह भी है कि वो पीएम मोदी, हिंदुत्व, भाजपा और आरएससी को आलोचना को लेकर जितने कंफर्टेबल परदेस में नजर आते हैं, उतना शायद स्वदेश में नहीं आते। इसमें दो राय नहीं कि मोदी और संघ की बेधड़क आलोचना कर राहुल ने अपनी एक राजनीतिक जमीन पुख्ता की है। हालांकि उनकी यह आलोचना हमेशा तार्किक हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन समर्थ को गरियाने की हिम्मत दिखाना भी साहस का प्रतीक माना जाता है। दरअसल, अमेरिका में भी राहुल कुछ वैसा ही बोलेंगे, जैसा कि उन्होंने यूके दौरे के समय बोला था, यह अपेक्षित ही था। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें पीएम और सरकार की आलोचना का पूरा अधिकार है। लेकिन मुद्दे की बात करते करते उनकी गाड़ी कब पटरी से उतर जाए, यह कहना मुश्किल है। जब देश में दो राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी वक राहुल विदेश क्यों गए, इसका कोई ठीक ठीक जवाब नहीं है सिवाय इसके कि यह भी एक प्रायोजित एजेंडे का हिस्सा था। उनकी यात्रा आधिकारिक नहीं थी। अमेरिका में बसे टैकनोक्रैट और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पहले ही कहा था कि राहुल की यह यात्रा निजी है। लेकिन इस निजी यात्रा को भी इस ढंग से डिजाइन किया गया था ताकि उसका अलग राजनीतिक संदेश जाए और राहुल जो भी कहें, उस पर दुनिया खासकर भारत में जमकर बवाल मचे। वैसा ही हुआ भी। कुछ बातें जो राहुल ने कही, वो पहले भी कहे जा चुके हैं। मसलन भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, भारत एक विचार नहीं है, कई विचारों से बना है, नरेन्द्र मोदी से अब कोई नहीं डरता वगैरह। लेकिन राहुल ने सबसे खतरनाक बयान भारत में सिखों की धार्मिक आजादी को लेकर दिया और इस बयान के समर्थन में अमेरिका में बैठे आंतक सिख नेता गुरुपतवंतसिंह पन्नू ने जिस ढंग से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, वह वाकई चिंतित करने वाली है। राहुल ने जो बात कही थी, वह भी बहुत चलताऊ तरीके से थी। वॉशिंगटन डीसी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा- हमे बसे पहले समझना होगा कि लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। उसी कार्यक्रम में उन्होंने एक सिख व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि लड़ाई इस बात की है कि एक सिख होने के नाते क्या उन्हें भारत में अपनी पागड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी? सिख होने के नाते इन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी? सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए ये लड़ाई है। बहुत गैरजिम्मेदारी से की गई इस टिप्पणी में राहुल ने यह नहीं बताया कि ऐसा कौन सा सिख उन्हें मिला, जिसने कहा हो कि भारत में वह पागड़ी नहीं बांध सकता या फिर कड़ा पहन कर गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। वैसे भी मर्यादा का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारे में मत्था टेक सकता है। राहुल ने जो कहा सो कहा, लेकिन उस बयान पर आंतकी पन्नू का जो बयान आया, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। पन्नू ने कहा- वॉशिंगटन डीसी के जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह बात कही, वहां कई खालिस्तान समर्थक सिख बैठे हुए थे। राहुल ने भारत में सिखों के साथ भेदभाव की बात कहकर हमारे संगठन सिख फॉर जस्टिस' को खालिस्तान पर वैश्विक जनमतसंग्रह की मांग का न्यायसंगत उद्घारा है। यही नहीं पन्नू ने यह भी कहा कि राहुल के बयान ने इस बात को सही सिद्ध किया है कि भारत में सिखों के साथ 1947 से ही भेदभाव होता आया है। इससे पंजाब को भारत से अलग करने के लिए जनमतसंग्रह की हमारी मांग का औचित्य ही सिद्ध होता है। हालांकि राहुल के अमेरिका में दिए इस बयान को कांग्रेस के श्रद्ध राजनीतिक स्वाधों के चलते खालिस्तान समर्थक जनरैलसिंह भिंडरावाले को शह दी थी। उसी भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था। इस अलगाववाद का नतीजा न केवल इंदिरा गांधी बल्कि पूरे देश ने भुगाता।

जम्मू में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण और भाजपा

आंकारेश्वर पांडेय

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जिस संजौली मस्जिद का निर्माण 1960 से पहले हुआ था और उसमें अवैध निर्माण भी 2010 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय शुरू हुआ, उसको लेकर विवाद आज अचानक इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे सांप्रदायिक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का मामला बताया है। लेकिन दरअसल यह मसला न तो सांप्रदायिक है, और न ही कानून व्यवस्था का, बल्कि यह सीधे सीधे राजनीतिक मामला है जिसे जम्मू-कश्मीर में इसी महीने हो रहे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

संजौली मस्जिद का विवाद तब उभरा जब कुछ हिंदू संगठनों ने इसके अवैध निर्माण का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मस्जिद का निर्माण बिना प्रशासनिक मंजूरी के हुआ और इसे एक मंजिला से पांच मंजिला तक बढ़ा दिया गया। इस मुद्दे ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ध्यान भी आकर्षित किया, जहां ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी जांच की मांग की। प्रशासन ने विवाद को निर्यात करने के लिए सख्त कदम उठाए। बुधवार को जब मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, तो शिमला में तनाव बढ़ गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई। जिला दंडाधिकारी ने संजौली क्षेत्र में सभी प्रकार के धार्मिक और भड़काऊ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया।

अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान इस मामले को और भड़का रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश जनार्थना का कहना है कि मस्जिद का निर्माण 1960 से पहले हुआ था, लेकिन अवैध विस्तार 2010 में हुआ। वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में न देखने की अपील की है।

संजौली मस्जिद विवाद अदालत में है, जहां मस्जिद प्रबंधन से इसके विस्तार के बारे में सवाल किया गया है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि इस विस्तार से सामाजिक तनाव और सुरक्षा खतर पैदा हो रहे हैं।

संजौली मस्जिद विवाद का संबंध जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से भी जोड़ा जा



रहा है। वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक महादेव चौहान का मानना है कि इस समय इस विवाद को उठाने का एक अहम उद्देश्य हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिल सकता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में हो रहे पहले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस विवाद को एक संवेदनशील मुद्दा बनाकर उभारा जा रहा है, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव तीन चरणों में होंगे 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ घोषित होंगे। 2018 में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार गिरने के बाद से यहाँ कोई निर्वाचित सरकार नहीं रही है।

संजौली मस्जिद विवाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने और इसे संघ शासित प्रदेश बनाया जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है, जिनमें से जिसमें जम्मू क्षेत्र में 6 नई सीटें जुड़ी हैं और अब वहाँ कुल 43 सीटें हो गयी हैं।

पश्चिमी हिमालय पर्वत-शृंखला में बसे हिमाचल प्रदेश की 1170 कि.मी. लंबी सीमाओं में से उत्तर में जम्मू-कश्मीर, दक्षिण में हरियाणा, पश्चिम में पंजाब, पूर्व में तिब्बत (चीन), तथा दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड से

लगाती हैं। हिमाचल प्रदेश के चम्बा और काँगड़ा जिले तो सीधे जम्मू कश्मीर से लगते हैं, जबकि उना, चम्बा, सोलन, विलासपुर, काँगड़ा जिले पंजाब से। सोलन, सिरमौर जिले हरियाणा से लगते हैं, तो किन्नौर, शिमला, सिरमौर उत्तराखण्ड से। वैसे हिमाचल का सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश से भी लगता है। उधर किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले भी जम्मू कश्मीर के निकट चीन (तिब्बत) से लगते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद को जम्मू-कश्मीर के चुनाव में लाभ लेने के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके मुताबिक इस विवाद का एक अहम उद्देश्य हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र को दो सीटें जीती थीं। अब संजौली मस्जिद विवाद का उपयोग करके बीजेपी जम्मू क्षेत्र में हिंदू मतदाताओं का भरपूर समर्थन पाने का प्रयास कर रही है।

यदि संजौली मस्जिद विवाद के चलते हिंदू मतदाता जम्मू क्षेत्र में एकजुट होते हैं, तो हिंदू बहुसंख्यक सीटों पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सकती है। वैसे भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बीजेपी ने राष्ट्रवाद, सुरक्षा और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसका लाभ उसे जम्मू में मिल सकता है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी राम माधव का दावा है कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अगली सरकार राष्वादिओं की बनेगी। उन्होंने

जम्मू रीजन में 35 सीटें और कश्मीर में 10 सीटें जीतने यानी 35+10 का फॉर्मूला पेश किया है।

इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने राज्य में अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा उठाया कांग्रेस भी राज्य की बहाली की बात कर रही है, लेकिन वह अनुच्छेद 370 पर सीधा रुख अपनाने से बच रही है।

जम्मू के मुस्लिम बहुल पंच जिलों—डोडा, राजौरी, पुंछ, रामबन, और किश्तवाड़—में 16 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षित हैं, जिन पर बीजेपी को जीत का भरोसा है, लेकिन बाकी 11 सीटों पर मुकाबला मुश्किल है। जम्मू में 35 सीटें जीतने के बीजेपी के लक्ष्य में यही मुस्लिम बहुल जिले सबसे बड़ी चुनौती हैं, जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है। 2014 के विधानसभा चुनावों में जम्मू की 37 सीटों में से 25 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इनमें से उपरोक्त मुस्लिम बहुल जिलों में उसे महज 6 सीटें मिली थीं, वह भी मुस्लिम वोट बंटने से पहले। पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन चुनौती पेश कर रहा है। इन दलों ने यहां चार से सात सीटें जीती थीं। तो अब जम्मू रीजन की 43 सीटों में बीजेपी को आरक्षित और हिंदू बहुल सीटों पर जीतने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मुश्किल है।

उधर कश्मीर घाटी में बीजेपी ने कभी कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इस बार पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी घाटी में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है, जिनके जीतने की संभावना है। साथ ही गुलाम नबी आजाद और इंजीनियर राशिद जैसे नेताओं के साथ गठजोड़ कर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों को लेकर यदि बीजेपी जम्मू क्षेत्र में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने में सफल रहती है, तो बीजेपी को 35 सीटों तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और 35+10 फॉर्मूले के तहत बीजेपी अगर जम्मू की 35 और कश्मीर की 10 सीटें जीतती है, तो यह राज्य के चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है।

पुराण दिग्दर्शन

परिचयाध्याय



प्रमाण-संग्रहाध्याय: (दूसरा अध्याय)

गतांक से आगे... (श्रीराग की बार महल्ल 3 पौड़ी 4)-(17) कुदरत वेद पुराण कतेबों। (राग असाबरी की बार महल्ल 3 श्लोक 3) (18) जुग जुग आपो अपना धर्म सोध देखो पुराण। (राग बिलाबल महल्ल 1 शब्द 4 मुक 6)-(19) जो शरण पड़े तिनकी पत राखे, जाय पूछड वेद पुराणी है।

(राग मारू हलहला 4 सोहले-शब्द 6 तुक 6) (20) शास्त्र वेद पुराण पुकारें धर्म करहु खद करम दृढ़या। (राग बिलाबल महल्ल 5 शब्द 5 तुक 6) (21) स्मृति शास्त्र वेद पुराण पारब्रह्म का करें बखान। (राग गौड़ी महल्ल 5 शब्द 17 तुक 2) (22) अगे गंजल अटल सिख संगत सब न्हाचे। नित पुराण वांचिये ब्रह्मा मुख गावे।। (सवैया महल्ल 5 के सवैया 20)

ग्रन्थ साहिब के अधिक प्रभाण इसलिये उद्धृत किये गये हैं कि कुछ दिनों से हिन्दूधर्मक्षक इस

ऐतिहासिक सम्प्रदाय में भी अहिन्दू भावों का सन्निवेश हो चला है।

जिस प्रकार वेदानुयायियों में आर्यसमाजी और कुराननुयायियों में अहमदी लोग मान्यदन्त अर्थ लगाकर अपने निजी ख्यालत को जबर्दस्ती धार्मिक चोला पहिनाने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार सिक्खों में भी अकाली नामक फिरका ग्रन्थ साहिब की मन्मानी व्याख्या करके हिन्दुत्व से बचना चाहता है। यह तीनों फिरके अपने जागों के आदिम अक्षर की समानता के अनुसार विचार में भी प्रायः समता रखते हैं, भेद केवल इतना है कि एक ने वेद का, दूसरे ने कुरान का और तीसरे ने ग्रन्थ साहिब का नाम घर कर टट्टी की ग्राइ में शिकार खेलना आरम्भ कर रक्खा है। पंजाब में भ्रमण करते हुवे हमें अकालियों से भी लोहा लेना पड़ता है, अतः एतद्देशीय उपदेशकों के लाभार्थ यह विस्तार किया गया है।

क्रमशः ...

योगेश कुमार गोयल

आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर कुछ भारतीय ही आज भले ही अंग्रेजी बोलने में अपनी आन, बान और शान समझते हों परन्तु सच यही है कि हिन्दी ऐसी भाषा है, जिसे आज दुनिया के अनेक देशों में भी सम्मानजनक दर्जा मिल रहा है और हमारी राजभाषा हिन्दी प्रत्येक भारतीय को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिला रही है। हिन्दी विश्व की प्राचीन, समृद्ध एवं सरल भाषा है, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। हिन्दी भाषा को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए ही प्रतिवर्ष 14 सितम्बर का दिन 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है और अगले 15 दिनों तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हिन्दी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितम्बर



को ही क्यों मनाया जाता है और इसे मनाए जाने की शुरुआत कब हुई?

दरअसल भारत बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उस दौरान हमारे यहां की भाषाओं पर भी अंग्रेजी दासता का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यही कारण रहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी को 'जनमानस की भाषा' बताते हुए वर्ष 1918 में आयोजित 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' में इसे भारत की राजभाषा बनाने को कहा था। सही मायने में तभी से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास

हिन्दी दिवस

शुरू हो गए थे। जब देश आजाद हुआ तो सर्वप्रथम 12 सितम्बर 1947 को संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने के प्रावधान का प्रस्ताव गोपालस्वामी आयरंगर ने रखा था, जो स्वयं एक अहिन्दीभाषी दूरदर्शी नेता थे। सभा की 12 से 14 सितम्बर तक चली तीनदिवसीय बहस में कुल 71 लोगों ने हिस्सा लिया था। लंबे विचार-विमर्श के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 (1) में हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में अंकित कर दिया गया, "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।" इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद हिन्दी को हर

क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा के अनुरोध पर 1953 से देशभर में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को ही मनाए जाने के लिए इसी दिन का चयन इसीलिए किया गया क्योंकि हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा देने के लिए पहली बार 14 सितम्बर 1949 को ही संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था, इसलिए इस दिवस के आयोजन के लिए इसी तारीख को श्रेष्ठ माना गया। 14 सितम्बर 1953 को जब हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में लागू कर दिया गया तो गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के लोगों ने इसका पुर-जुदो विरोध शुरू कर दिया और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मनोमस्तिष्क में रच-बस गई अंग्रेजी भाषा की वकालत करने लगे।

अफगान महिलाओं के हाल पर सब मौन क्यों हैं?

केएस तोमर

तालिबान शासन अपने पतन की ओर है, फिर भी वह समाज में महिलाओं की पहचान मिटाने में लगा है, जो उसके अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग होने का प्रमुख कारण है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सुधार की कम गुंजाइश के साथ इसे 'धीमी गति से मौत = महिलाओं और लड़कियों की दुर्दशा' के रूप में चिह्नित किया है। लोग पीड़ित हैं, क्योंकि तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता और वित्तीय मदद नहीं मिल रही है। भविष्य में भी यही स्थिति रह सकती है, क्योंकि वहां पहले से ही इतने कड़े प्रतिबंध हैं कि महिलाओं को चेहरा समेत पूरा शरीर ढकना होता है, यहां तक कि वे घर से बाहर आना भी नहीं निकाल सकतीं। इन राजकीय प्रतिबंधों की वजह से महिलाएं सार्वजनिक रूप से गीत नहीं गुनगुना सकतीं एवं कुरान नहीं पढ़ सकतीं। साथ ही उनके पतले, तंग और छोटे कपड़े पहनने पर भी पाबंदी है। यही नहीं, कानून ने महिलाओं के घर में भी तेज आवाज में बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। इस डर से कि उनकी आवाज चहारदीवारी से बाहर न निकल जाए। शासनादेशों की वजह से बाल विवाह और जबरन विवाह बढ़ गए हैं। वहीं, जिन महिलाओं ने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें प्रताड़ित किया गया। दुनिया को इसके खिलाफ मुखर होना पड़ेगा। बाद में तीव्र प्रतिक्रिया जताने पर भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

दूसरी तरफ, चीन का ध्यान अपने शिनजियांग क्षेत्र में अतिवादी गतिविधियों को रोकने पर है। चीन अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंखें मूंदकर तालिबान से संबंध बनाए रखना चाहता है। तालिबान के प्रति चीन का दृष्टिकोण दर्शाता है कि उसके यहां हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी



दुनिया का कोई देश हस्तक्षेप या आलोचना न करे। तालिबानी शासन से जुड़कर चीन अपनी पश्चिमी सीमाओं को स्थिर कर भू-राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में वर्चस्व पाना चाहता है, खासकर जब अमेरिका और उसके सहयोगी अफगानिस्तान से पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा, चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों के दोहन पर भी है। महिलाओं के प्रति तालिबान के नजरिये को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासी नाराजगी है। जबकि चीन का ध्यान अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने पर है, इसलिए वह अफगानिस्तान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की अनदेखी कर रहा है। बीजिंग मानवाधिकारों के मुद्दों से ज्यादा आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को तबज्जो देता है। चीन अफगानिस्तान से होकर अपने बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्ट का विस्तार कर इस क्षेत्र में अपने निवेश को सुरक्षित करना चाहता है।

कूटनीतिक और मानवीय आधार पर अफगानिस्तान में महिलाओं की रक्षा करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत को शांति वार्ता में महिलाओं को शामिल करने की वकालत कर संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता वाली पहल का

समर्थन करना चाहिए। अफगान महिलाओं को भारत में पढ़ने के लिए वित्तीय मदद और छात्रवृत्ति देने से भविष्य में वहां सशक्त महिला नेतृत्व तैयार हो सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर भारत अफगान महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी सहायता उपलब्ध करवा सकता है। अतीत में भी भारत ने स्कूल और अस्पतालों के निर्माण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे समाज कार्यक्रमों के जरिये अफगान महिलाओं की सहायता की है। तालिबान के पुनरुत्थान से उपजी चुनौतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महिला अधिकारों की लगातार वकालत करना भारत की उनके प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हालांकि मौजूदा हालात अफगान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की मांग करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र व मानवाधिकार संगठनों समेत विश्व समुदाय ने महिलाओं के प्रति तालिबान के व्यवहार की निंदा की है, लेकिन ये प्रयास नाफाफी हैं। संयुक्त राष्ट्र को अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तालिबान की शत्रुता के चलते वह संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव काफी कम हो गया है। मानवीय मदद बेशक जरूरी है, लेकिन यह दीर्घकालीन समाधान नहीं है और तालिबान के प्रतिबंधों की वजह से अति जरूरतमंदों तक मदद पहुंच ही नहीं पाती। बयानबाजी के परे वह संगठित वैश्विक दबाव बनाने की जरूरत है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे का लाभ उठाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन महिलाओं के लिए सुरक्षित मार्ग तलाशना चाहिए, जो

अफगानिस्तान छोड़ना चाहती हैं और संकट में रहने वालों को शरण देनी चाहिए।

वर्ष 2001 में अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल करने और अफगान महिलाओं को अत्याचार से मुक्त दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बेहतर नेतृत्व किया था। लेकिन 2021 में अमेरिका ने स्थिरता व समावेशी सरकार सुनिश्चित किए बिना अपने सैनिकों को वापस बुलाकर महिलाओं को उन्हीं ताकतों के हवाले कर दिया, जिससे सुरक्षा दिलाने का वादा किया गया था। इसलिए तालिबान द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अमेरिका को फिर से आगे आना होगा। अमेरिका आर्थिक मदद, कूटनीतिक पहल के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संगठित करके तालिबान पर दबाव बना सकता है। अमेरिका को अपनी विदेश नीति के केंद्र में अफगान महिलाओं के हितों को रखना चाहिए। अफगान महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले माफिस लीनो दंपती का कहना है कि तालिबान ने जीवन छोड़कर अफगान महिलाओं के लगभग सभी मानवाधिकार छीन लिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होते ही वहां की महिलाओं का बुरा वक्त शुरू हो गया और विश्व समुदाय, खासकर अमेरिका खुद को चौराहे पर पाता है, जहां वह अपनी नैतिक और रणनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर जूझ रहा है। अरब देशों ने भी अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को मानवाधिकारों से ऊपर रखते हुए तालिबान को बर्बरता को मौन स्वीकृति प्रदान की है। अब विश्व समुदाय को इस भावना के साथ आगे आना चाहिए कि अफगान महिलाओं के अधिकारों का लड़ाई पूरी दुनिया की महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष है। अफगान महिलाओं को अकेले न छोड़ते हुए पूरी विश्व विरादरी को उनके लिए लड़ना होगा। यह दांव बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी चुप रहने के गंभीर परिणाम होंगे।

आज का इतिहास

- 1926 प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बस्तियों की स्थापना करने वाले लोकानां संधि औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की गई थी।
- 1951 पर्यटन विश्वविद्यालय में एक बीज रहित तरबूज विकसित किया गया है यह गोल है और इसका वजन लगभग 8 से 10 पाउंड होगा, इसे अगले साल तक देश के कुछ हिस्सों में बिक्री पर देखा जा सकता है।
- 1954 एक शीर्ष गुप्त परमाणु परीक्षण में, एक सोवियत टीयू -4 बमवर्षक ने टोत्कोए गांव के उत्तर में सिर्फ 40 किलोटन सैनिकों और 10,000 नागरिकों को परमाणु पतन के लिए उतारा गया।
- 1959 प्रथम मानव निर्मित वस्तु लूना 2 चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त भूमि है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के दो महाशक्तियों के बीच अंतरिक्ष की दौड़ को बुला रही है, जिसमें चंद्रमा तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया है।
- 1959 तत्कालीन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान लूना-2 चांद्र पर उतरने वाला पहला यान बना।
- 1964 द लंदन डेली हेराल्ड प्रकाशन को समाप्त कर उसकी जगह द सन को प्रकाशित किया गया।
- 1966 न्यूनतम वेतन \$ 1.40 प्रति घंटे को नई दर पर है जिसमें सार्वजनिक स्कूलों और नर्सिंग होम, साथ ही निर्माण उद्योग में शामिल होंगे।
- 1972 पश्चिम जर्मनी और पोलैंड ने राजनयिक संबंधों पर समझौता किया।
- 1975 एलिजाबेथ एग सेटन जन्मजात राज्यों के पहले जन्मजात नागरिक बन गए थे जिन्हें विहित किया गया था।
- 1979 अफगान राष्ट्रपति नूर मुहम्मद तारकी की हत्या हाफिजुल्लाह अमीन की हत्या के बाद की गई, जो नए राष्ट्रपति बने।
- 1982 जब लेबनान के राष्ट्रपति-चुनाव बशीर गेमायाल की हत्या कर दी गई थी, जब फलांगे के बेरुत मुख्यालय में बम विस्फोट हुआ था।
- 1982 हॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री और मोनाको की राजकुमारी ग्रेस केली की मॉटे कालों में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी।
- 1985 सोवियत संघ ने 25 ब्रितानी राजनयिक को जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया।

आरक्षण खत्म करने की डेडलाइन राहुल गांधी ने बताई

अभिनय आकाश

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। वाराणसी में जन्में कबीर दास जी की ये वाणी वहां से 177 किलोमीटर दूर के क्षेत्र अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी आत्मसाध कर लेते तो जाति की राजनीति पर उनका इतना जोड़ न रहता। इन दिनों राहुल गांधी अमेरिका में अपने आरक्षण खत्म करने की टाइमलाइन बताने को लेकर विवादों में हैं। वैसे तो सिख, आरएसएस समते कई सारे मसलों पर ऐसी बातें कर दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पारा आसमान पर चढ़ा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल जब भी विदेश जाते हैं तो देश में विवादों की आंधी आ जाती है। इस बार भी यही हो रहा है। राहुल गांधी के जिन बयानों को लेकर देश में हंगामा हो रहा है उसके केंद्र में धर्म, चुनावी प्रक्रिया और आरक्षण है। वहीं आरक्षण खाड़ी जिसको लेकर दावा है कि 2024 के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार बहुमत पाने से रोक दिया।

देश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का दबदबा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल कर आरक्षण खत्म कर देगी, और ये बात चुनावी मुद्दा बन गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दोहरा रहे हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की वो हर कीमत पर रक्षा करेंगे। एक तरफ

जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति की राजनीति के सहारे बीजेपी से पार पाने की जुगत में लगे हैं। वहीं चुनाव समाप्त होने के बाद जाति और आरक्षण का मुद्दा संसद में भी गुंजाता नजर आया। संसद में कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पर चर्चासमय उस वक्त देखने को मिला जब सदन में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया था।

पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया। हर चुनावी रैली में संविधान की कॉपी लेकर भाषण दिया। यहां तक की वो सांसद के तौर पर शपथ लेने गए तो उस वक्त भी उनके हाथों में संविधान की कॉपी नजर आई। उसी संविधान को खत्म करने को लेकर वॉशिंगटन डीसी के जार्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जब राहुल से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। उसके जवाब में राहुल ने जो बातें कही उसने हिंदुस्तान में बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करने के बारे में तब सोचेंगे जब भारत में सब एक समान होंगे। भारत में अभी सब समान नहीं हैं। आरक्षण ही वो मुद्दा है जिसे कांग्रेस को 99 तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन उन्होंने जब इसके खत्म करने के फैसले की शर्त का जिक्र किया तो मायावती से लेकर बीजेपी ने उन पर वही आरोप लगाने शुरू कर दिए।

राहुल गांधी की पारिवारिक जड़ें और उन्हें कश्मीर का कौल ब्राह्मण कहा जा सकता है या उन्हें पारसी कहा



जाए इसके लेकर मीडिया या यूं कहें कि सोशल मीडिया में विमर्श लगातार चलता रहता है। राजीव गांधी पारसी पिता फिरोज गांधी की संतान हैं जो सेक्युलर मूल्यों पर जीते थे। नेहरू परिवार में जाति और धर्म का सवाल दो पैमानों पर मापा जाता है। नेहरू, फिरोज और सोनिया के पैमाने पर राहुल की जाति का पता लगाया जा सकता है। फिरोज के पैमाने पर राहुल पारसी हो सकते हैं। भारतीय परंपरा में आमतौर पर जाति पिता के नाम से निर्धारित की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी की जाति क्या है? राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपनी जड़ें नेहरू परिवार से जोड़ते हैं तो इसके पीछे क्या वजह है?

राहुल गांधी के नाना यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अपने नाम के साथ पंडित लगाते थे।

मौका पड़ने पर अपना जनेऊ भी दिखाते थे। इंदिरा हो या राजीव खुद को ब्राह्मण ही मानते हैं। राजस्थान चुनाव के दौरान गांधी-नेहरू परिवार के पुरोहित से जब ये पूछा गया था कि उनके दादा फिरोज गांधी तो पारसी थे, तो क्या दादा की जगह दादी इंदिरा गांधी का गोत्र हो सकता है। इस पर पुरोहित ने बताया कि पारसी समुदाय में पत्नी को हिंदू धर्म की तरह पति का गोत्र नहीं दिया जाता है। ऐसे में पीहर के गोत्र का इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने भी पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का गोत्र कौल दत्तात्रेय ही रखा,

लेकिन गांधी सरनेम और खानदान की सियासी हैसियत के चलते इस परिवार के सामने इससे पहले खुद का गोत्र बताने की राजनीतिक मजबूरी कभी नहीं आई थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खुद के हिंदू गोत्र का प्रमाण दे दिया था। गांधी-नेहरू परिवार के पुरोहित के जरिए राहुल ने अपना गोत्र सार्वजनिक करवा दिया था। राहुल दत्तात्रेय कौल बाटम्पण हैं।

ये तो आप सभी को पता है कि राहुल गांधी राजवी और सोनिया की संतान हैं। राजीव और उनके भाई संजय फिरोज और इंदिरा गांधी की संतान हैं। फिरोज का जन्म एक पारसी परिवार में 12 सितंबर 1912 को हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूद घांडी था। हालांकि कितानें कहती हैं कि घांडी फिरोज का कुलनाम था

पारसी धर्म में जाति का नाम था। जिसे उन्होंने आजादी की लड़ाई में कूदने के बाद गांधीजी से प्रभावित होने के कारण बदलकर गांधी कर लिया। फिरोज गांधी ने 8 सितंबर 1960 का निधन दिल्ली के धन वेल्सिंगटन अस्पताल में सुबह के वक्त अंतिम सांस ली थी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। बर्टिल फाक की किताब फिरोज- द फॉरगट्टन गांधी के अनुसार फिरोज के निधन के बाद कुछ पारसी परंपराओं को भी फॉलो किया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से किया गया था। फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित भी की गई थी। जबकि कुछ अस्थियों को दफना दिया गया। जहां इन अस्थियों को दफनाया गया, वहां ही एक कब्र भी बनाई गई। 1980 में मेनका गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी यहां आई थीं। उसके बाद परिवार का कोई सदस्य इस कब्रिस्तान में नहीं आया। इस कब्रिस्तान की देखभाल एक चौकीदार करता है। कब्रिस्तान में कुआं और एक मकान के अलावा चौकीदार के रहने के लिए दो कमरे भी बने हुए हैं। देखभाल के अभाव में फिरोज गांधी सहित उनके पूर्वजों की कब्र जर्जर हो चुकी हैं। प्रयागराज में पारसी मजार की देख-रेख करने वाले बाबूलाल ने साल 2019 में एक निजी मीडिया समूह से बात करते हुए कहा था कि हुल गांधी इस मजार पर आए थे और 10 साल पहले उन्होंने फूल-माला भी अर्पित की थी। 2019 में उन्होंने कहा था कि इस घटना को 10 साल हो चुके हैं।

पूरब के देशों से रिश्ते बढ़ाना आज के समय की मांग

शोभना जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की आसियान क्षेत्र स्थित सिंगापुर और ब्रुनेई यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए खासी अहम मानी जा रही है बल्कि इससे खास तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए 'आसियान' की केंद्रीय भूमिका को और बल मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से जुड़े दक्षिण पूर्व एशिया के दो अहम देशों की यह यात्रा इसलिए और भी अहम मानी जा रही है कि हाल के वर्षों में खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम के मद्देनजर ऐसा लग रहा था कि भारत का दक्षिण एशिया पर से ध्यान अपेक्षाकृत कुछ बंट रहा है। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री की सिंगापुर, ब्रुनेई यात्रा से इस तरह के स्पष्ट संकेत दिए गए कि खाड़ी के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए न केवल उतना ही अहम है बल्कि अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के चलते रिश्तों की मजबूती आज की जरूरत भी है। इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर के इस बयान से डिप्लोमैसी की बारीकियों को समझें जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि खाड़ी और दक्षिण एशिया क्षेत्र- दोनों ही भारत के लिए अहम हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हाल की आसियान देशों की यात्रा इसी डिप्लोमैसी की सूचक मानी जा सकती है। इसी पृष्ठभूमि में अगर दुनिया के अनेक देशों की तरह इस क्षेत्र में भी चीन की बढ़ती सक्रियता की बात करें तो इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के पहले ब्रुनेई और फिर सिंगापुर दौरे से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। अहम बात यह है कि चीन की तरफ झुकाव वाले ब्रुनेई की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा आर्थिक रिश्तों को और बढ़ाने के साक्ष्य रक्षा क्षेत्र सहित समुद्री सुरक्षा के अहम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर देने की सहमति से द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिल सकती है। ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर में एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है और भारत की एकट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ मजबूत सामरिक रिश्ते रखने वाले ब्रुनेई के चीन के साथ आर्थिक रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं भारत के साथ उसका व्यापार घटा है, बावजूद इसके पिछले दशक में भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार दोगुना बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार 65 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 120 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। सामरिक दृष्टि से आसियान का केंद्र माने जाने वाले ब्रुनेई के साथ आर्थिक, सुरक्षा सहित इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में पहल कर कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी चीन के लिए खासी चुनौतीपूर्ण है। चीन दक्षिण चीन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां आए दिन नौवहन की निर्बाध गतिविधियों को बाधा पहुंचाता रहता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडराता रहा है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की आसियान क्षेत्र स्थित सिंगापुर और ब्रुनेई यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए खासी अहम मानी जा रही है बल्कि इससे खास तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए 'आसियान' की केंद्रीय भूमिका को और बल मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से जुड़े दक्षिण पूर्व एशिया के दो अहम देशों की यह यात्रा इसलिए और भी अहम मानी जा रही है कि हाल के वर्षों में खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम के मद्देनजर ऐसा लग रहा था कि भारत का दक्षिण एशिया पर से ध्यान अपेक्षाकृत कुछ बंट रहा है। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री की सिंगापुर, ब्रुनेई यात्रा से इस तरह के स्पष्ट संकेत दिए गए कि खाड़ी के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए न केवल उतना ही अहम है बल्कि अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के चलते रिश्तों की मजबूती आज की जरूरत भी है। इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर के इस बयान से डिप्लोमैसी की बारीकियों को समझें जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि खाड़ी और दक्षिण एशिया क्षेत्र- दोनों ही भारत के लिए अहम हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हाल की आसियान देशों की यात्रा इसी डिप्लोमैसी की सूचक मानी जा सकती है। इसी पृष्ठभूमि में अगर दुनिया के अनेक देशों की तरह इस क्षेत्र में भी चीन की बढ़ती सक्रियता की बात करें तो इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के पहले ब्रुनेई और फिर सिंगापुर दौरे से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। अहम बात यह है कि चीन की तरफ झुकाव वाले ब्रुनेई की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा आर्थिक रिश्तों को और बढ़ाने के साक्ष्य रक्षा क्षेत्र सहित समुद्री सुरक्षा के अहम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर देने की सहमति से द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिल सकती है। ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर में एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है और भारत की एकट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण साझेदार है। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ मजबूत सामरिक रिश्ते रखने वाले ब्रुनेई के चीन के साथ आर्थिक रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं भारत के साथ उसका व्यापार घटा है, बावजूद इसके पिछले दशक में भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार दोगुना बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार 65 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 120 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। सामरिक दृष्टि से आसियान का केंद्र माने जाने वाले ब्रुनेई के साथ आर्थिक, सुरक्षा सहित इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में पहल कर कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी चीन के लिए खासी चुनौतीपूर्ण है। चीन दक्षिण चीन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां आए दिन नौवहन की निर्बाध गतिविधियों को बाधा पहुंचाता रहता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडराता रहा है।

ऊर्जा स्वालंबत की दिशा में सार्थक कदम है सूर्य घर योजना

विकास शर्मा

हाल के दिनों के तीन समाचारों ने मेरा ध्यान खींचा और इसमें मुझे भविष्य की तैयारी का खाका नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रीमंडल ने ई- ड्राइव योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत बिजली चलित वाहनों (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को बढ़ावा देने के लिए अनुदान तथा 88 हजार 500 ई- चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन की तैयारी है। वहीं दिल्ली में आयोजित आटोमोटिव मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन के कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दो वर्षों में पेट्रोल- डीजल कारों के समान ही बिजली चलित वाहनों को कीर्तमान होंगे। इन तीनों समाचारों से विद्युत ऊर्जा और विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और महत्व को समझा जा सकता है। भारत में विगत एक दशक में जिस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास नजर आ रहा है यह दर्शाता है कि यह तैयारी आने वाले तीन ड्ज्चार दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। पर्यावरण संतुलन तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने परिणाम केंद्रित प्रयासों को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन (कोयल, गैस, डीजल तथा लिग्नाइट) की भागीदारी को वर्तमान 54.5 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।



भागीदारी को बढ़ाने वाला है। दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर 75 हजार 21 करोड़ रूपए व्यय किया जा रहा है। इसमें भारी भरकम अनुदान के साथ ही आवश्यक विद्युत अधोसंरचना का विकास भी शामिल है। योजना के तहत देश के एक करोड़ घरों की छतों पर एक से तीन किलोवॉट के सौर पैनल स्थापित होंगे जो लघु बिजली संयंत्र की भांति कार्य करेंगे। अनुमान है कि तीन सौ यूनिट प्रतिमाह तक बिजली मुफ्त प्राप्त करने के साथ ही हितग्राही अपनी उत्पादित शेष बिजली को ग्रीड के माध्यम से राज्य बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे। योजना की प्रारंभिक सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 13 फरवरी 2024 को शुरू होने के छह माह के अंदर एक करोड़ 28 लाख से अधिक हितग्राहियों ने सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए पंजीयन कराया है।

योजना हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ ही रोजगार सृजन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण, परिवहन,आपूर्ति समेत संचारण और संधारण से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के 17 लाख नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। ऊर्जा पर खर्च कम होने से घरेलू बजट बढ़ने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में आम नागरिक की अप्रत्यक्ष भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी।

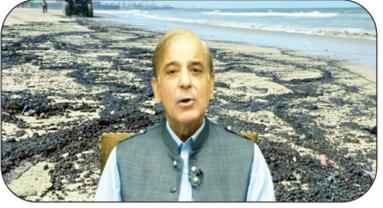
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की तात्कालिकता तथा इसके पीछे की दूरदर्शिता को भी समझा जा सकता है। देश की प्रगति और समृद्धि को समझने के लिए प्रति व्यक्ति आय की तरह प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी एक आधार है। साल 1947 में खपत 18.47 किलोवॉट ऑवर (केव्हीएच) से आज 2024 में 72 गुणा अधिक 1327 केव्हीएच पहुंच चुका है जिसके तेजी से बढ़ते हुए आगले 5-6 वर्षों में 1500 केव्हीएच तथा वर्ष 2050 में 2500 केव्हीएच प्रति

पाकिस्तान के हाथ सच में लगा अलादीन का चिराग?

अभिनय आकाश

आपने अपने बचपन में अलादीन और जादुई चिराग की कहानी तो खूब सुनी होगी। अलादीन का चिराग एक हिंदी का प्रचलित मुहावरा भी है जिसके कहने का अर्थ कोई ऐसी चीज का हाथ लगना जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। जैसे काश मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता तो मैं गरीबी को दुनिया से दूर कर देता। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो अगर सच हो तो भारत के पड़ोसी देश की गरीबी जरूर दूर हो सकती है। पाकिस्तान को अलादीन सरीखा चिराग हाथ लग गया है। समुद्री सीमा में तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। कहा ये जा रहा है कि ये तेल और गैस का भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। ये खबरें ऐसे समय में आई हैं जब दक्षिण एशियाई देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने डॉन न्यूज टीवी को बताया है कि इन भंडारों में देश की किस्मत बदलने की क्षमता है। हालाँकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार मिला है।

ऐसे देश जो समुद्र से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं उनके कुछ हिस्सों पर उनके मछुआरे से लेकर बाकी सारे उद्भाग किए जाते हैं। बंदरगाह भी बनाए जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि कुछ दूरी तक का आधिपत्य उनके पास हो। इसको लेकर काफी विवाद भी हुए। बहुत सारे देश कई बार एकदम करीब करीब आते थे। फिर इसको लेकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई। कोई भी देश उसके तट से लेकर 80 किलोमीटर तक 100 प्रतिशत कंट्रोल उसी देश की रहेगी। 200 किलोमीटर तक उसका एक और बॉर्डर होगा जिसमें आधिपत्य तो उसी देश का होगा लेकिन इस दायरे में अगर दूसरे अन्य देशों को आना होगा तो इनके सहमति से वो आवागमन कर सकते हैं। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में गैस और तेल का भंडार पाया गया है। इस ऑयल रिजर्व को लेकर बात हो रही है कि अगर ये ठीक



ठीक उतना ही पाया जाता है, जितना अनुमान लगाया जा रहा है तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हो सकता है।

डॉन न्यूज टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने एक मित्र देश के साथ मिलकर तीन साल का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद तेल और गैस भंडार का पता चला। इस सर्वेक्षण से पाकिस्तान ने जमाव का स्थान खोज लिया है। वेनेजुएला के पास 3 बिलियन बैरल से अधिक के साथ सबसे अधिक मात्रा में तेल भंडार है, इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक हैं। ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे अधिक अप्रयुक्त शेल तेल भंडार है।

पाकिस्तान उच्च ऊर्जा और ईंधन की कीमतों का खामियाजा भुगत रहा है। देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा अकेले पेट्रोलियम आयात पर खर्च करता है। तेल भंडार की कोई भी बड़ी खोज देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति से प्रभावित आबादी के लिए ईंधन और गैस सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचाएगा, जो इस जून में दो साल के उच्चतम 9.4 बिलियन तक पहुंचने से पहले फरवरी 2023 में घटकर 2.9 बिलियन रह गया था। एक्सप्रेस ट्रिव्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने पिछले साल ऊर्जा आयात पर 17.5 अरब डॉलर खर्च किए। सात साल में इसके दोगुना होकर 31 अरब डॉलर होने की संभावना है। वर्तमान में, देश 29 प्रतिशत गैस, 85 प्रतिशत तेल, 20 प्रतिशत कोयला और

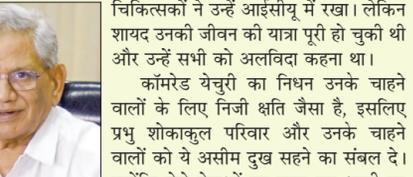
50 प्रतिशत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा करता है। पाकिस्तान को नीली अर्थव्यवस्था से लाभ हो सकता है। तेल और गैस के अलावा, मूल्यवान खनिज और तत्व समुद्र से निकाले जा सकते हैं। हालाँकि, कुएँ खोदने और तेल निकालने में कई साल लग सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42 हजार करोड़ का खर्च आएगा। इसके बाद समुद्र की गहराई से इसे निकालने में 4-5 साल लग सकते हैं। अगर रिसर्च सफल रही तो तेल और गैस की निकालने के लिए कुएँ लगाने और बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी।

वे कहते हैं कि अपनी मुर्गियों को अंडों से निकलने से पहले न गिनें। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को उत्पाहित करना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने तेल भंडार से लाभ मिलने में कई साल लग सकते हैं। डॉनन्यूज टीवी से बात करते हुए, तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (ओपारा) के पूर्व सदस्य मुहम्मद आरिफ ने कहा कि देश को आशावादी होना चाहिए लेकिन यह कभी भी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं है कि भंडार उम्मीद के मुताबिक खोजा जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या ये भंडार पाकिस्तान को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे, यह आकार और उत्पादन की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। यदि यह गैस भंडार है, तो यह एलएनजी आयात का स्थान ले सकता है और यदि यह तेल भंडार है, तो आयातित तेल का स्थान ले सकते हैं। पिछले महीने, पाकिस्तान सरकार ने तेल और गैस की खोज के लिए 20 अफगनी ब्रॉकों की नीलामी करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। इससे पहले जुलाई में, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि देश में तेल और गैस भंडार की खोज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए दक्षिण एशियाई देश को अगले तीन वर्षों में स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से 5 अरब डॉलर का निवेश हासिल करना की उम्मीद है।

चर्चित वामपंथ युगद्रष्टा का अलविदा कहना...

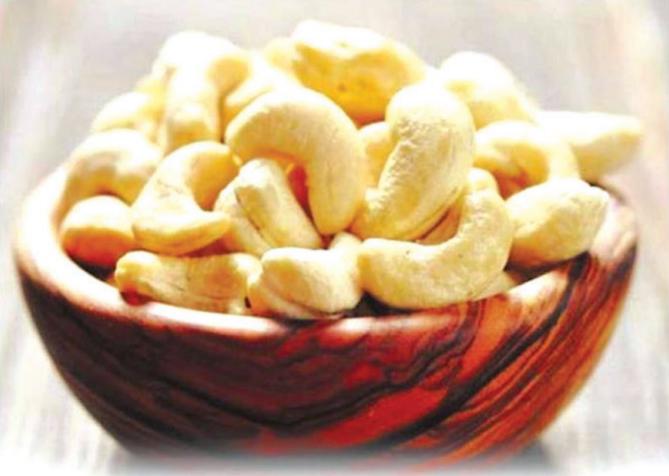
डॉ. रमेश ठाकुर

वर्चितां, दलितों, किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की एक ओर बुलंद आवाज 12 सितम्बर को शांत हो गई। वामपंथ के प्रमुख युगद्रष्टा कॉमरेड सीताराम येचुरी के रूप में देश ने एक बेहद संवेदनशील, भावुक, ऊर्जा से भरे दूरदर्शी नेता को खो दिया। जीवन के 72वें वसंत पूरे करके येचुरी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित 'रुम्ह' अस्पताल में अंतिम सांस लेकर नश्व संसार को



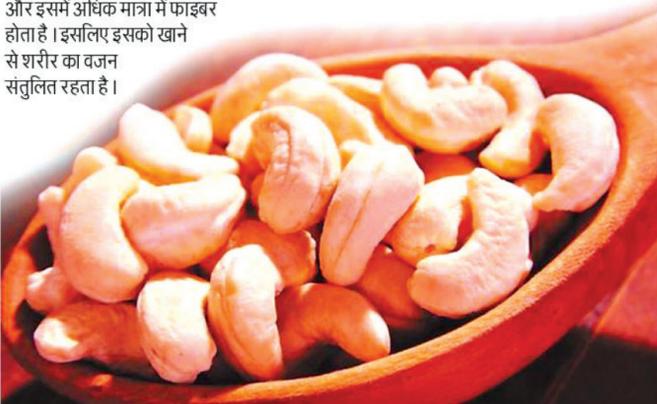
अलविदा कहकर अपने परमधाम को चले गए। उनका निधन देश की राजनीति खासकर वामपंथी, फासिज्म विरोधी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक की मौजूदा हिचकोले लेती व्यवस्था के लिए गहरे आघात जैसा है। येचुरी वामपंथ सियासत में ही लोकप्रिय नहीं थे, वे भारतीय राजनीति के भी चर्चित चेहरे थे। यूपीए-एक और यूपीए-दो में उनका बोलबाला था। कांग्रेस हुकूमत के दोनों टर्मों में वाम नेता कांग्रेस को समर्थन नहीं देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन येचुरी ने सभी को मनाया और बिना शर्त बाहर से समर्थन देने को अपने साथियों को राजी किया। तभी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वो चहते बने, राहुल ने कई मंतीबा सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी कि उन्होंने राजनीति की तमाम एबीसीडी सीताराम येचुरी से सीखीं।

सीताराम येचुरी का संपूर्ण जीवन जनसरोकारों के लिए सबसे जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति की भूमिका निभाते बीता। इमरजेंसी से आगे भी जेल में डाला गया। इंदिया गांधी की हुकूमत को आगे बढ़कर ललकारने वाले वह एक मात्र ऐसे नेता थे, जिन्होंने इंदिया गांधी के आंखों में आंखे डालकर न सिर्फ उनकी आलोचनाएं की थी, बल्कि उनका इस्तीफा भी संरेआम मांगा था। लेकिन वह ऐसा दौर था जब प्रशंसा और आलोचनाओं की कद्र हुआ करता थी। अब आलोचना करने वाले को या तो देशद्रोही कहा जाता है, या फिर उनके पीछे जांच एजेंसियां लगावा दी जाती हैं। सीताराम येचुरी निःसंदेह भारतीय राजनीति में बेहतरीन दौर जीकर गए हैं। वह अपने जीवनकाल के अंत तक राजनीति में एक्टिव रहे। बीते कुछ समय से वह 'एक्यूटे रेस्पिरैटरी टैक्ट इंफेक्शन' से पीड़ित थे, जिसने उनके शारीरिक कें आंगों को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया था। पिछले माह 19 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। हालात में कुछ सुधार हुआ भी था, लेकिन 10 सितंबर को स्थित कुछ ज्यादा बिगड़ी तो



उत्तम औषधि है काजू

मेवे का प्रयोग उत्तम औषधि के रूप में किया जाता है। क्योंकि मेवा स्वाद की नहीं बल्कि सेहत की दृष्टि से भी उत्तनी ही फायदेमंद है। काजू में मैग्नीशियम पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप को कम करने में और दिल के दौरों को रोकने में मदद करता है। काजू कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित रखता है। काजू में प्रोटीन की मात्रा काफी होती है जो बॉडी व हड्डियों को मजबूत बनाती है। चाहे मिठाई में काजू कतली हो या फिर दूसरे पकवानों में काजू का इस्तेमाल। काजू किसी भी आम डिश को शाही बना सकता है। अब जब काजू हमें इतना पसंद ही है तो इससे होने वाले लाभ के बारे में भी जान लेना चाहिए। काजू में प्रोटीन, खनिज लवण, लौह, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, और तांबा का अच्छा स्रोत है। काजू का तेल, स्कवी मस्सा और रिगवर्म के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप प्रतिदिन 7-10 काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू खाने से मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखता है। काजू में मोनो सैचुरेटेड फैट होता है जो की दिल को स्वस्थ रखता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। काजू में एंटी ओक्सिडेंट भी होते हैं जो कैंसर से बचाव करता है। काजू पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे भूख भी कहीं अधिक लगती है। आंतों में भरी गैस कम किया जा सकता है। काजू में पाए जाने वाले फाइबर-केमिक्लस कैंसर और दूसरे बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। जिन महिलाओं को मेनोपॉज है उन्हें तनाव, स्ट्रेस होना एक आम सा समस्या है। उन महिलाओं को रोजाना एक काजू खाना चाहिए। काजू में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। काजू में अधिक एनर्जी होती है और इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है। इसलिए इसको खाने से शरीर का वजन संतुलित रहता है।



खीरे में हैं सेहत व सौन्दर्य के अनगिनत गुण

खीरा सेहत के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। ये सेहत के साथ-साथ सौंदर्य में बहुत फायदेमंद होता है। कम फेट व कैलोरी से भरपूर खीरे का सेवन आपको कई रोगों से बचाने में सहायता करता है। खीरे को आप कई तरह से खा सकते हैं, जैसे सलाद, जूस, सेंडवीच, या यून ही नमक छिड़क कर भी खा सकते हैं। खीरे के स्वास्थ्यवर्धक और सौन्दर्यवर्धक गुण दोनों अनगिनत होते हैं जैसे आयुर्वेद के अनुसार खीरा, पित्त, रक्त पित्त दूर करने वाला तथा रक्तविकार और मूत्र कच्छ नाशक रूचिकर फल है। खीरे के प्रयोग से पेट तथा जिगर की जलन शांत होती है। खीरे का नियमित सेवन से मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। यह हृदय रोगी के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार खीरा में जो स्टैराल नाम का योगिक होता है वह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। खीरे में कैलोरी कम और फाइबर उच्च मात्रा में होता है। इसलिए मीठे डे में भूख लगने पर खीरा खाने से पेट दैर तक भरा हुआ रहता है। आयुर्वेद के मुताबिक पेट में गमी होने के वजह से मुंह से बदबू निकलता है, खीरा पेट को शीतलता प्रदान करने में मदद करता है।



गर्भाशय में रसौली के लक्षण जान इस तरह करें घरेलू उपचार

बिगड़ते लाइफस्टाइल में महिलाओं में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, इन्हीं में से एक फाइब्रोइड यानी रसौली। फाइब्रोइड या रसौली की गांठें महिलाओं के गर्भाशय में या उसके आसपास बनती हैं। इस बीमारी के ज्यादातर लक्षण न होने के कारण महिलाओं को इसका पता नहीं चल पाता। एक शोध के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं रसौली का शिकार होती हैं। वैसे तो अक्सर यह समस्या 30 से 50 की उम्र में देखने को मिलती है लेकिन गलत खान-पान के कारण यह समस्या इससे कम उम्र में हो जाती है। मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन स्तर ज्यादा होने के कारण उन्हें इसका खतरा सबसे अधिक होता है। इस बीमारी के कुछ सामान्य लक्षणों से इसकी पहचान करके आप इससे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं फाइब्रोइड के लक्षण और इसे दूर करने के कुछ घरेलू उपाय।



फाइब्रोइड या रसौली के लक्षण

पीरियड्स के दौरान भारी ब्लिडिंग
अनियमित पीरियड्स
पेट के नीचे के हिस्से में दर्द
प्राइवेट पार्ट से खून आना
कमजोरी महसूस होना
प्राइवेट पार्ट से बदबूदार डिस्चार्ज
पेट में अचानक दर्द कब्ज
पेशाब रुक-रुककर आना

फाइब्रोइड या रसौली के घरेलू उपाय

केस्टर ऑयल

दिन में 2 बार केस्टर ऑयल और अदरक के रस को मिला कर लें। सुबह और रात में सोने से पहले इसका सेवन इस बीमारी को दूर करता है।

लहसुन

रसौली की समस्या होने पर खाली पेट रोज 1 लहसुन का सेवन करें। लगातार 2 महीने तक इसका सेवन इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है।

बरडॉक रूट

यह जड़ी-बूटी एस्ट्रोजन को डिटॉक्स कर गर्भाशय फाइब्रोइड को कम करने में मदद करती है। एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण से भरपूर इस जड़ी-बूटी का सेवन इस समस्या और कैंसर के खतरे को कम करता है।

सेब का सिरका

गर्म पानी के साथ सुबह शाम सेब का सिरका पीने से फाइब्रोइड की समस्या दूर होती है। इसके अलावा इसका सेवन फाइब्रोइड से होने वाले पेट दर्द को भी दूर करता है।

चेस्टबेरी

यह हर्ब हार्मोन संतुलन करके एस्ट्रोजन के कम स्तर को बनाए रखने और सूजन को कम करने में मदद करता है। चेस्टबेरी हर्ब से बने मिश्रण की 25-30 बूंदों को दिन में दो से चार बार लेने से आपको यह समस्या दूर हो जाएगी।

हल्दी

एंटीऑक्सिडेंट गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। यह फाइब्रोइड की ग्रोथ को रोक कर कैंसर का खतरा कम करता है।



दांतों में कैविटी की समस्या को इन तरीकों से करें दूर

सफेद और सूंटेर दांत व्यक्ति की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इनके बिना खाना खाने का कोई मजा नहीं आता। ऐसे में दांतों की सही देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग के गलत खान-पान या सही तरीके से दांतों की देखभाल न करने पर इनमें कैविटी यानी कीड़ा लग जाता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। कई बार कीड़ा लगने से इतना दर्द होता है कि उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कई लोग दवाइयां और ट्रीटमेंट का सहारा भी लेते हैं। जो की बहुत महंगा है। ऐसे में आप नैचुरल तरीके से भी दांतों में लगे कैविटी को आसानी से हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में।

क्या है कैविटी

शक्करयुक्त खाद्य पदार्थों यानि बिरिकट्स, चॉकलेट्स, आलू, केला को खाने से मुंह में अम्ल बनने लगते हैं। इससे दांतों में धीरे-धीरे छोटे-छोटे छिद्र बन जाते हैं। बाद में इन्हीं छिद्रों में कैविटी या कीड़ा लगत जाता है। इसके अलावा दांतों में संक्रमण होने पर भी कैविटी बन सकती है। इसका इलाज न करावाने पर दांतों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। पीड़ित व्यक्ति को दांत खाने पड़ सकते हैं।

ऐसे करें कैविटी से बचाव

मिठाई, कैंडी और चॉकलेट खाना कम करें। शक्करयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। ज्यादा मिठदा फल न खाएं। सोडा न पीएं। इसमें 12 से 40 ग्राम चीनी की मात्रा होती है जो कि दांतों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। खाने के बाद कुल्ला करें। तेल और मसालेदार भोजन न खाएं। ज्यादा गर्म या ठंडा खाना खाने से बचें।

कैविटी लगे दांतों का घरेलू इलाज

नारियल या सूरजमुखी का तेल कीड़ा लगे दांतों में तेल भरना सबसे बेस्ट घरेलू तकनीक है। इसके लिए आप नारियल तेल या सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में कम से कम 20 मिनट तक रखें। इसके बाद कुल्ला करें और ब्रश कर लें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपको खुद ही फर्क

दिखाई देने लगेगा।

फ्लोराइड

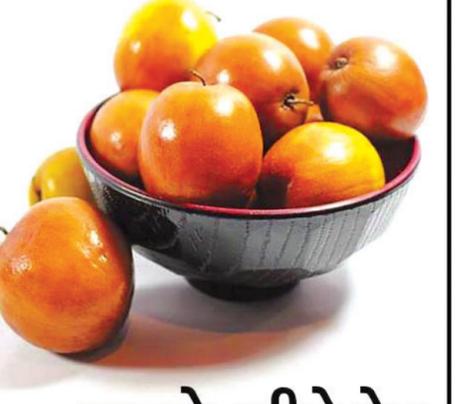
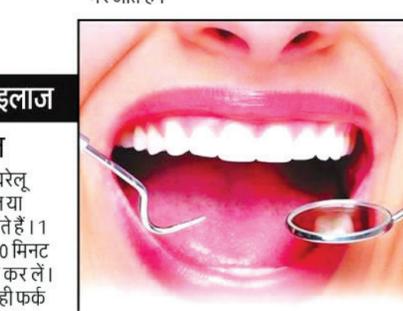
यह एक तरह का प्राकृतिक खनिज पदार्थ है। यह दांतों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होने देता है। दांतों को सुरक्षित रखने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करें जिस में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो। इसके साथ ही दूध पेस्ट से रोजाना दो बार ब्रश करें।

हींग

हींग का इस्तेमाल करने से भी दांतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं। हींग के पाउडर को पानी में डालकर उबालें। इसके ठंडा होने पर इस पानी से कुल्ला करें। रोजाना ऐसा करने से दांत के कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही दांतों में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलेगा।

प्याज के बीज

दांतों के कीड़े को नष्ट करने के लिए प्याज के बीजों का इस्तेमाल करें। इसके बीजों को चबाने से कीड़े जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आप चाहें तो प्याज को बारिक काट कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरे बारिक कटा प्याज डालकर उसमें इसमें थोड़ा-सा तेल डालकर कम आंच पर गर्म करें। इससे निकलने वाले धुएं को मुंह में लेने से भी कीड़े मर जाते हैं।



खट्टे-मीठे बेर में समाएं कई गुण

आयुर्वेद के अनुसार बेर दिल की सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। बेर खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने की आशंका कम हो जाती है। बेर खाने से बार-बार प्यार लगने की शिकायत भी दूर होती है। खट्टे-मीठे बेर में पोटेशियम, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस और खनिज पदार्थ आदि भी होते हैं। इन सभी तत्वों से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गर्मियों में पीथे सुषुप्तावस्था में प्रवेश कर जाते हैं व उस समय पतियां अपने आप ही झड़ जाती हैं तब पानी की आवश्यकता नहीं के बारबर होती है। इस तरह बेर अधिक तापमान तो सहन कर लेता है लेकिन शीत ऋतु में पड़ने वाले पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। क्योंकि इसमें कम पानी व सूखे से लड़ने की विशेष क्षमता होती है। जिस तरह नींबू और संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसी तरह बेर में भी। बेर में अन्य फलों के मुकाबले विटामिन-सी और एंटीऑक्सिडेंट ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसके सेवन से त्वचा बढ़ती उम्र तक जवां बनी रहती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा खट्टे फलों से 20 गुना तक अधिक होती है। बेर की गुठली को घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से कनीनिका प्रवाह ठीक हो जाता है। आंखों से बहने वाला पानी भी बंद हो जाता है। बेर के पत्तों को पानी में काफी समय तक उबालकर काढ़ा बनाकर छानकर पीने से शरीर की बढ़ती चर्बी कंट्रोल हो जाती है। चेचक में बेर के पत्तों का रस भैंस के दूध के साथ रोगी को देने से रोग का वेग कम होता है। बेर में 6 ग्राम पत्तों के चूर्ण को 2ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर रोगी को खिलाने से भी 2-3 दिन में चेचक खत्म होने लगता है।



भाजपा ने राहुल के आरक्षण संबंधी बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन

मुंबई। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लोगों को राहुल गांधी के लिए आरक्षण विरोध मानसिकता के बारे में बताने के लिए प्रदर्शन करना जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने भाजपा पर फर्जी खबरें फैलाने और नौटंकी करने का आरोप लगाया। छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र के आवास मंत्री अतुल सावे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान, भाजपा की दहिस्त सीट से विधायक मनीषा चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आरक्षण का विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि गांधी का आरक्षण विरोधी रुख उजागर हो गया है।

हरियाणा में अब पार्टी दोगुनी ताकत से चुनाव लड़ेगी : आप

चंडीगढ़। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी (आप) की हरियाणा इकाई के प्रमुख शुशील गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राज्य में चुनाव प्रचार करेगी जहां लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "हम अब दोगुनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी जल्द ही हरियाणा में अपना अभियान शुरू करेंगे।" हरियाणा में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आप अकेले अपने दम पर लड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा काल में विकास ठप हो गया है। लोग उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पांच अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं।"

केजरीवाल के बाहर आने से खुश नहीं है कांग्रेस?

नई दिल्ली। केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। कांग्रेस ने कहा कि फिरोहाल, यह सिर्फ जमानत है। कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी इसे सिर्फ एक प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानती है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि हम इसे इससे अधिक किसी चीज के रूप में नहीं देखते हैं। अभी तक आरोपों से बरी होने की कोई बात सामने नहीं आई है। अंतिम फैसला अभी भी लिखित है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली सशर्त जमानत के बाद आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी।

हरियाणा में 25 को पहली रैली को संबोधित करेंगी मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती हरियाणा में 25 सितंबर को पार्टी की पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। देश के उप राष्ट्रपति रहे देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को मायावती हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के साथ मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। बसपा नेताओं के अनुसार, इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बसपा और इनेलो का गठबंधन भाजपा और कांग्रेस को अपनी ताकत का अहसास कराएगा। इस गठबंधन के जीते नेता ही हरियाणा में सरकार के गठन में अहम रोल निभाएंगे। फिलहाल वहां मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनाव प्रचार का दायित्व संभाले हुए हैं। बसपा इस बार हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन के तहत बसपा ने 37 और इनेलो ने 53 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं।

पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजय पुरम होगा : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में पोर्ट ब्लेयर के नए नाम का एलान किया गया। अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विजन के तहत देश को औपनिवेशिक पहचान से मुक्त करने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। अब गुलामी का एक और निशान मिटा दिया गया है। उन्होंने लिखा कि पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाना मना है...

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाले मामले में फंसे सीएम केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है क्योंकि करीब 156 दिन जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।

शुक्रवार, 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ अरविंद केजरीवाल द्वारा जमानत की मांग करने वाली और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने के लिए एकत्र हुई। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां अलग-अलग फैसले सुनाया है। न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले में कोई फाइल तक नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पेश होते रहेंगे।

न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में न्यायमूर्ति सुर्यकांत से सहमत जताई। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो।

मालूम हो कि पिछले 156 दिनों से केजरीवाल जेल में बंद थे और आज कोर्ट द्वारा रिहाई देने का फैसला न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के लिए राहत की बात है।



जानकारी के अनुसार, पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट (जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच) ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। हालांकि, सीबीआई मामले के कारण उनकी कैद जारी रही।

जानें क्या-क्या शर्तें

- उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी न करें।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे।
- किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
- किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकते।
- आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में कोई फाइल तक नहीं देख सकते।
- ट्रॉयल कोर्ट में पेश होते रहेंगे।

केजरीवाल मामले पर न्यायमूर्ति उज्वल ने कहा कि सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है, उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो।

केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आप ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया,

"सत्यमेव जयते"। न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां ने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं रह सकती है। जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत

मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें घोर आपत्तिजनक हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोकती हैं।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर न्यायिक अनुशासन के कारण टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे, जबकि 22 महीने तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।

आज फिर सत्य की जीत, केजरीवाल की जमानत पर आप में खुशी की लहर, बांटी मिठाईयां

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित आप नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर जश्न मनाया और मिठाई बांटी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। सिसोदिया ने आगे कहा, एक बार पुनः नमन करता हूँ बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था। सिसोदिया ने कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भाजपा ने हजारों तरह की साजिश रची। उन्हें जेल में डाला। आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जिनके कारण आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। राघव चड्ढा ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेंडियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। वहीं, आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ दो लोग आज जेल में बचे थे, इसलिए जमानत तय थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिवस कि केजरीवाल को जेल में रखने के लिए केंद्र सरकार को एजेंसी ये षड्यंत्र कर रही थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, आप परिवार को बधाई। मजबूत बने रहने के लिए बधाई। हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूँ।

केजरीवाल की जमानत पर भाजपा बोली हर सोमवार और गुरुवार होना होगा पेश जेल वाला से अब बेल वाला मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आड़ना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सशर्त बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तें अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा। वह विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। वह गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते।

भाटिया ने आगे इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। कोर्ट में उनकी दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दुष्टाचार का भंडाफोड़ किया। अरविंद केजरीवाल को किसी भी अदालत से कभी राहत नहीं मिली और न ही कोई आरोप रद्द कर दिया गया है। भाटिया ने कहा कि आप को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और लोग उनसे इस्तीफा लेंगे।

दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पद छोड़ने का आग्रह करते हुए



कहा कि हम आग्रह करते हैं कि यदि उनमें कोई नैतिकता बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आप के पास कोई नैतिक चरित्र नहीं है। वे बहुत दूर हैं। सचदेवा ने आगे कहा कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि आप जमानती बलबल बन गई है और वहां अरविंद केजरीवाल का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है, उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी। सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, मुकदमा चलेगा और उन्हे शीघ्र लम्बी सजा होगी। केजरीवाल याद रखें वह अब लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गये हैं और उन्हे भी जमानत मिली थी और वह शीघ्र सजा पा कर फिर जेल जायेंगे। जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते -- केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हे अब मुख्य मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वह मुख्य मंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों- अगर वो सच्चे हैं तो यह शर्त क्यों- इस्तीफा दे ?

स्टील प्रमुख समाचार

पहले टेस्ट के लिए भारत ने चेन्नई में शुरू किया अभ्यास

चेन्नई। बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया शुक्रवार को चेन्नई पहुंची। बतौर मुख्य कोच गौतम गंभीर और गेंदबाजी कोच मोनै मोर्केल को यह पहली टेस्ट सीरीज होगी जिसमें उनका लक्ष्य भारतीय टीम को जिताना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय खिलाड़ियों को कुछ तस्वीरें साझा की, जिनमें गंभीर और रोहित को उन्हे संदेश देते देखा गया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मुकाबला एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच कानपुर में 27 सितंबर से शुरू होगा। बीसीसीआई ने शुक्रवार को प्रेक्टिस सेशन की तस्वीरें साझा कीं। बोर्ड ने लिखा-उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीम इंडिया एक रोमांचक घरेलू सत्र के लिए अपनी तैयारी शुरू कर रही है।

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टीम से जुड़ गए। वह लंदन से सीधे चेन्नई पहुंचे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत गुवर्गार को ही यहां पहुंच गए थे। खिलाड़ी एक महीने से अधिक के ब्रेक के बाद मैदान पर लौटेंगे। अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को श्रीलंका के हाथों हार मिली थी। नए कोच गौतम गंभीर की यह पहली टेस्ट सीरीज है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने जा रही टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है। भारतीय टीम को इसके बाद यूजीलैंड से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज खेलनी है। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 68.52 प्रतिशत अंक लेकर शीर्ष पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया 62.52 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश 45.83 प्रतिशत अंक लेकर चौथे स्थान पर है।

सेंसेक्स 82,900 से नीचे आया निफ्टी में भी गिरावट

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में दो दिन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। शुक्रवार को इक्रिटी बेंचमार्क इंडेक्स, संसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ रिफॉर्ड ऊंचाई से नीचे फिसल गए। 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स 71.77 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट लेकर 82,890.94 पर बंद हुआ। संसेक्स में आज 82,653.22 और 83,092.93 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत टूटकर 25,356.50 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 25,292.45 और 25,430.50 के रेंज में कारोबार हुआ। संसेक्स के 30 शेयरों में से 11 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील संसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एचबीआई, एचसीएच टेक, नेस्ले इंडिया और टीसीएस के शेयर लाभ में रहे।

आर्थिक/वणिज्य/वित्त/प्रमुख समाचार

विश्व में कई गतिविधियां एक कालखंड के रूप में चलती रहती हैं। एक कालखंड के पश्चात चक्र कभी नीचे की ओर जाता है एवं एक अन्य कालखंड के पश्चात यह चक्र कभी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। विदेशी व्यापार के मामले में वर्ष 1750 तक पूरे विश्व में भारत की तूती-पीतनी रही है, परंतु इसके पश्चात यूरोपीयन देशों ने विस्तारवादी नीतियों के चलते अपने आर्थिक हित साधते हुए विभिन्न देशों पर अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन, फ्रान्स, डच जैसे देशों ने एशियाई देशों एवं कुछ अफ्रीकी भू भाग पर पर अपना कब्जा जमाया तो स्पेन आदि देशों ने अमेरिकी महाद्वीप पर अपना कब्जा जमाया। समय के साथ चक्र कुछ इस प्रकार चला कि वर्ष 1950 आते आते अमेरिका पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों की श्रेणी में

भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% से ज्यादा वृद्धि की क्षमता

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को सिंगापुर में एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर कहा कि भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से भी अधिक होने की क्षमता रखती है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष FY25 के लिए बताई गई 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से थोड़ा ज्यादा है। दास ने यह बयान ब्रेटन वुड्स कमेटी के वार्षिक फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम में दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत की वर्तमान विकास क्षमता लगभग 7.5 प्रतिशत से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि यह कार्यक्रम सिंगापुर में स्विस बैंक यूबीएस के सहयोग से आयोजित किया गया था। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, इस साल के अंत तक हम 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद कर रहे हैं। अप्रैल से जून तिमाही में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रही, जो पिछले साल की तुलना में कम थी।

दरअसल, अमेरिका ने पूंजीवादी नीतियों को अपनाकर अपने नागरिकों में केवल आर्थिक उन्नति को ही विकास के एकमात्र मार्ग के रूप में चुना था, इससे वहां के नागरिकों में किसी भी प्रकार से धन अर्जन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई एवं सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। परिवार व्यवस्था समाप्त हो गई जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि आज अमेरिका में नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, मेडिकेयर योजना, मेडिकेड योजना, प्रौढ़ नागरिकों को सुविधाएं एवं केंद्र (फेडरल) सरकार के कर्मचारियों को अदा की जा रही पेंशन, आदि योजनाएं सरकार द्वारा नागरिकों के हितार्थ अमेरिका में चलानी

चेन्नई में न्यूफैक्टरिंग प्लांट को निर्यात के लिए उपयोग की तैयारी

नई दिल्ली। अमेरिकी वाहन विनिर्माता कंपनी फोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि वह निर्यात के लिए वाहन बनाने हेतु अपने चेन्नई विनिर्माण संयंत्र का उपयोग करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बताया कि उसने इसकी सूचना तमिलनाडु सरकार को दे दी है। कंपनी ने 2021 में कहा था कि वह भारत में वाहनों का विनिर्माण बंद कर देगी, लेकिन अब उसने तमिलनाडु सरकार को एक आशय पत्र (एलओआई) दिया है, जिसमें निर्यात के लिए विनिर्माण हेतु चेन्नई संयंत्र का उपयोग करने के इरादे की पुष्टि की गई है। फोर्ड ने बयान में कहा कि यह घोषणा फोर्ड नेतृत्व और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान हुई बैठक के बाद की गई है। फोर्ड ने कहा कि इस रणनीतिक कदम के तहत कंपनी की महत्वाकांक्षी 'फोर्ड- विकास योजना' के तहत वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुविधा का पुनःनिर्माण किया जाएगा।

पड़ रही हैं। इन योजनाओं पर खर्च किए जा रहे 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि का लाभ करोड़ों अमेरिकी नागरिक प्रतिवर्ष उठा रहे हैं। यह राशि अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है। सुरक्षा की मद पर भी अमेरिका द्वारा 70,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च प्रतिवर्ष किया जाता है। भरोजगारी बोमा लाभ योजना पर भी भारी भरकम राशि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खर्च की जाती है। अमेरिका में सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण इस मद पर व्यय की जाने वाली राशि में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, साथ ही लगातार बढ़ रहा सुरक्षा खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की लगातार बढ़ रही राशि के बीच वर्तमान में कर की दरों में वृद्धि नहीं करने के कारण बजटीय घाटे पर

पौकरबाजी की मूल कंपनी में नजारा करेगी निवेश

नई दिल्ली। ईस्टपोर्ट्स कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज रियल मनी गैमिंग मंच पौकरबाजी की मूल कंपनी मूनशाइन टेक्नोलॉजी में 982 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। नजारा ने शुक्रवार को बयान में कहा कि वह सीधे के तहत मूनशाइन टेक्नोलॉजी में 831.51 करोड़ रुपये में 47.7 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। इसमें 592.26 करोड़ रुपये का नकद लेनदेन और 239.25 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर अदला-बदली व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था के साथ, बाजी गेम्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और संस्थापक नवकिरण सिंह सहित चुनिंदा निवेशकों और प्रबंधन कर्मियों को नजारा टेक्नोलॉजीज में 3.17 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। इसके अलावा, नाजारा 100 प्रतिशत अनिवार्य परिवर्तनीय की सदस्यता के लिए 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसे समझौते के तहत भविष्य में इक्रिटी में बदला जा सकता है।

अमेरिका में लगातार बिगड़ती आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

प्रह्लाद सबनानी

विश्व में कई गतिविधियां एक कालखंड के रूप में चलती रहती हैं। एक कालखंड के पश्चात चक्र कभी नीचे की ओर जाता है एवं एक अन्य कालखंड के पश्चात यह चक्र कभी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। विदेशी व्यापार के मामले में वर्ष 1750 तक पूरे विश्व में भारत की तूती-पीतनी रही है, परंतु इसके पश्चात यूरोपीयन देशों ने विस्तारवादी नीतियों के चलते अपने आर्थिक हित साधते हुए विभिन्न देशों पर अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन, फ्रान्स, डच जैसे देशों ने एशियाई देशों एवं कुछ अफ्रीकी भू भाग पर पर अपना कब्जा जमाया तो स्पेन आदि देशों ने अमेरिकी महाद्वीप पर अपना कब्जा जमाया। समय के साथ चक्र कुछ इस प्रकार चला कि वर्ष 1950 आते आते अमेरिका पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों की श्रेणी में

साथ ही वहां का सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल, अमेरिका ने पूंजीवादी नीतियों को अपनाकर अपने नागरिकों में केवल आर्थिक उन्नति को ही विकास के एकमात्र मार्ग के रूप में चुना था, इससे वहां के नागरिकों में किसी भी प्रकार से धन अर्जन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई एवं सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। परिवार व्यवस्था समाप्त हो गई जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि आज अमेरिका में नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, मेडिकेयर योजना, मेडिकेड योजना, प्रौढ़ नागरिकों को सुविधाएं एवं केंद्र (फेडरल) सरकार के कर्मचारियों को अदा की जा रही पेंशन, आदि योजनाएं सरकार द्वारा नागरिकों के हितार्थ अमेरिका में चलानी

पड़ रही हैं। इन योजनाओं पर खर्च किए जा रहे 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि का लाभ करोड़ों अमेरिकी नागरिक प्रतिवर्ष उठा रहे हैं। यह राशि अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है। सुरक्षा की मद पर भी अमेरिका द्वारा 70,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च प्रतिवर्ष किया जाता है। भरोजगारी बोमा लाभ योजना पर भी भारी भरकम राशि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खर्च की जाती है। अमेरिका में सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण इस मद पर व्यय की जाने वाली राशि में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, साथ ही लगातार बढ़ रहा सुरक्षा खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की लगातार बढ़ रही राशि के बीच वर्तमान में कर की दरों में वृद्धि नहीं करने के कारण बजटीय घाटे पर

दबाव बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक रिपोर्ट आफ द प्रेजीडेंट के अनुसार अमेरिका में वर्ष 2000 में 23,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बजट आधिक्य था जो वर्ष 2001 में घटकर 12,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया। परंतु, वर्ष 2002 में एक बार जो 15,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बजट घाटा प्रारम्भ हुआ तो इसके बाद से वह बढ़ता ही गया है। वर्ष 2009 में तो बजट घाटा बढ़कर 141,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया, वर्ष 2010 में 129,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2011 में 130,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2012 में 108,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2020 में 313,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2021 में 277,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2022 में 188,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है।

सदस्यता अभियान की सफलता सबकी जिम्मेदारी : जम्वाल



रायपुर। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल ने सदस्यता अभियान को लेकर बस्तर और सरगुजा संभाग के पदाधिकारियों के बैठक ली। इससे पूर्व दुर्ग, रायपुर व बिलासपुर संभाग की बैठक ले चुके हैं। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष किरण देव व मंत्री रामविचार नेताम, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, बस्तर संभाग प्रभारी रजनीश सिंह व महेश कश्यप, पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास मदी सहित पार्टी पदाधिकारी, बस्तर व सरगुजा सदस्यता अभियान के टोली के सदस्य मौजूद थे। शुक्रवार को जगदलपुर व अम्बिकापुर के जिला कार्यालय में आयोजित बैठक संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री जम्वाल ने कहा कि

सदस्यता अभियान की सफलता सबकी जिम्मेदारी है। हमें जिस तरह से आशातीत सफलताएं मिल रही हैं इसके लिए पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान की टोली लगी हुई है। हमने जो लक्ष्य तय किया है उसे पूर्ण होना ही सबकी सफलता को साबित करेगा। जिसके लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जुटा है। अभी तक सफलता हमें प्रेरित करने वाली है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कहा कि सभी जिलों से लेकर बृथ तक सदस्यता अभियान में हमें व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन्मयता से जुटा है। समाज के हर वर्ग का भाजपा के इस अभियान को समर्थन मिल रहा है। अभियान की सफलता के

लिए अधिक से अधिक सदस्य बनाने की अपील की है। जिससे की सदस्यता अभियान के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के मादरिशन में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। प्रत्येक बृथ-शक्ति केन्द्र व जिलावार हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि नयी पीढ़ी को अधिक से अधिक पार्टी विचारधारा से जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश सदस्यता अभियान संयोजक अनुराग सिंहदेव ने मरवाही में जिला पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जितना अधिक सदस्यता होगी उतना अधिक ही हम शक्तिशाली होंगे। हमारे लिए

यह संगठन का महाउत्सव है। जिसमें उसकी सहभागिता जरूरी है। सहप्रभारी नवीन मारकंडे ने सक्ती व मुंगेली जिले के बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिलेवार व विधानसभावार हमारी सभी बैठक संपन्न हो चुकी है। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी सदस्यता अभियान को सफल बनाने में हर मोर्चे पर जुटे हुए हैं। जल्द ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी प्रवास प्रदेश में होगा। जिससे की अभियान को और गति मिल सके।

जांजगीर चांपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय राजनितिक दल है

जिसका पूरा श्रेय भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं एवं समर्पित सदस्यों को जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं व सदस्यों के वजह से ही भाजपा की देश में तीसरी बार सरकार बनी है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के अंतर्गत आज रायगढ़ विधानसभा व जांजगीर-चांपा की संगठनात्मक बैठक ली साथ ही सदस्यता अभियान संबंधी आवश्यक दिशा, निर्देश देते हुए कहा कि सदस्यता अभियान का उद्देश्य देश के नागरिकों को देश हित राष्ट्र हित में कार्य करने हेतु सकारात्मक विचारधारा से जोड़ना है।

जिसके लिए हम सभी समर्पित एवं कटिबद्ध हैं। भाजपा के सक्रीय सदस्य एवं कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता अभियान की प्रगति पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सदस्यता टोली के सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अब तक सदस्यता अभियान में मिली सफलता पर व आगामी कार्ययोजना पर बिन्दूवार चर्चा होगी।



रतनपुर महामाया मंदिर का होगा कार्याकल्प, कॉरिडोर के लिए बनाई गई योजना: साहू

रायपुर। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर कॉरिडोर भव्य बनाने दृष्टिकोण को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता की व्यक्त किए हैं। अयोध्या, काशी और महाकाल में देखे गए स्मारकीय विकासों की प्रतिध्वनि करते हुए, मंत्री ने ग्यारहवीं शताब्दी के महामाया मंदिर के लिए भी इसी तरह के परिवर्तन का संकल्प लिया है। साहू ने आज 13 सितंबर, 2024 को निर्माण भवन में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में के.पी. महादेवस्वामी, सीएमडी (एनबीसीसी), आर.एन. शिना, सीजीएम (एनबीसीसी) अपनी टीम के साथ मौजूद थे और उन्होंने मंत्री को विस्तृत योजना के बारे में जानकारी दी। इससे पहले, प्रदेश की करोड़ों जनता की आस्था का सम्मान करते हुए, मंत्री ने रतनपुर में कॉरिडोर बनाने की मांग रखी थी और केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जगदीश सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रतनपुर का महामाया मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य इस पवित्र स्थल को इस तरह से विकसित करना है कि इसके समृद्ध इतिहास का सम्मान हो और देश भर में इसकी छवि बढ़े।

एनबीसीसी ने महामाया मंदिर कॉरिडोर के लिए एक विकास योजना प्रस्तुत की। तथा यह सुनिश्चित करने के लिए मंदिर की भव्यता इसकी सुविधाओं से मेल खाती है, विकास योजना में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं—

- व्यापक अवसंरचना विकास—यौति कक्ष, भागवत मंच, प्रार्थना स्थल, कार्यालय, संग्रहालय इत्यादि।
- आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएँ— होटल, दुकानें, और कई पार्किंग क्षेत्रों के साथ बड़ी हुई पहुँच।
- मंत्री का दृष्टिकोण महामाया मंदिर को एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभारना है। इस पहल का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक मंदिर को संरक्षित करना है, बल्कि आगंतुकों को पुनर्जीवित और समृद्ध

अनुभव प्रदान करना भी है। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में, हम देश के धार्मिक स्थलों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका ध्यान रखा गया है और तीर्थयात्रा और धार्मिक पर्यटन को आसान बनाने के लिए उनका विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत देश भर के धार्मिक स्थलों का व्यापक विकास हुआ है। मंत्री का समर्थन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एकीकृत माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की एक बड़ी पहल है।

रायपुर, दुर्ग-गिलाई, बिलासपुर और कोरबा की सड़कों पर जल्द लैडिगी ई-बसें

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनाती के लिए पीएम-ई-बस सेवा योजना की स्थिति का जायजा लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परिव्ययों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए, मंत्री ने किसी भी चुनौती का निवारण करने और शहरी परिवहन और स्थिरता के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ को पीएम-ई-बस सेवा योजना की पहली किस्त में 30.19 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो चार शहरों—रायपुर, दुर्ग-गिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई-परिवहन को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ के लिए, ई-बसों की खरीद के लिए स्विच किया गए सभी बुनियादी ढाँचे के प्रस्ताव, जिसमें चार्जिंग के लिए सिविल डिपो अवसंरचना और बिजली अवसंरचना का विकास शामिल है।

रायपुर पश्चिम में विकास कार्यों की लगी झड़ी

पूर्व मंत्री राजेश मृगत ने दो वार्डों के लिए के लाखों के कार्य स्वीकृत - पूर्व में भी कई अन्य वार्डों के लिए करोड़ों के विकास कार्य किया जा चुके हैं स्वीकृत

रायपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मृगत प्रतिदिन अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने इस कड़ी को आगे बढ़ते हुए बाल गंगाधर तिलक वार्ड और एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड में लाखों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की।

मृगत ने कहा कि विकास कार्यों का यह सिलसिला हमने वाला नहीं है जब तक मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ हर दिन जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। उन्होंने कहा कि जनता ने 5 साल तक कांग्रेस का कुशासन झेला है। लेकिन अब वह वक्त



रायपुर शहर को कुछ नई सौगातें मिलने जा रही हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा को भी इसके तहत लाभ मिलेगा।

इन् कार्यों में मिली मंजूरी— बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य

अधोरसंरचना मद स्वीकृत कार्य बमलेश्वरी नगर में उद्यान निर्माण 10 लाख
आदर्श नगर में सड़क में नाली निर्माण 10 लाख
महतारी चौक के पास स्मार्ट सुलभ शौचालय निर्माण 10 लाख
वार्ड अंतर्गत आदर्श आंगनवाड़ी भवन निर्माण 10 लाख
अशोकनगर ऊपर पर में सड़क नाली निर्माण 10 लाख
मुख्यमंत्री अधोरसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण से स्वीकृत विकास कार्य बमलेश्वरी नगर में कंक्रीट सड़क निर्माण 8 लाख
एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य

अधोरसंरचना मद से स्वीकृत कार्य अशोकनगर में आदर्श आंगनवाड़ी भवन निर्माण 10 लाख
हरिओम किराना से नाले तक पाइपलाइन विस्तार 10 लाख
विकास नगर से कोटा गार्डन जाने हेतु पुलिया निर्माण 3 लाख
विकास नगर तिरंगा चौक में भवन निर्माण 5 भारत माता चौक में स्मार्ट स्लिप शौचालय निर्माण 10 लाख
प्रीत नगर मुक्तिधाम में सेट निर्माण 10 लाख
विधायक निधि से स्वीकृत कार्य विकास पवार क्षेत्रीय समाज गुदियारी के अशोकनगर स्थित सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर निर्माण 10 लाख

घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य अमला बना रहा छूटे हुए का आयुष्मान कार्ड



रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले का स्वास्थ्य अमला घर-घर पहुंचकर छूटे हुए का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर ने आगामी 10 दिनों तक खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पहुंचकर कर्मचारी अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाएं। इसके लिए प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री मिथिलेश चौधरी ने बैठक लेकर जिले में आयुष्मान योजना का लाभ अधिक से अधिक दिलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर-घर पहुंचकर नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बना रही हैं। इसमें पांच लाख रूपए तक इलाज की सुविधा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री मिथिलेश चौधरी ने बताया कि नागरिकों के निरंतर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर को

रायपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को किया जाना है। इस बार भी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा नियमित रूप से समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है तथा सुक्ष्मता के साथ लोक अदालत की तैयारी पर निगरानी रखी जा रही है। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबंधी, बैंक संबंधी, चेक बाउंस संबंधी, यातायात संबंधी, जलकर, बीएसएनएल. नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधी, धारा 138 एनआईए. संबंधी मामलों को चिन्हित कर रखा जा रहा है तथा शासन की योजनाओं का लाभ भी आम जन को प्राप्त हो, इस के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग के साथ बैठक कर उन्हें नेशनल लोक अदालत के दिन हितप्रियों को प्राप्त होने वाले लाभ को वितरण करने निर्देशित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा रायपुर के सभी नगरवासियों से अपील की है।

राजधानी की सड़कें होगी बेहतर, मरम्मत के लिए मिले 12 करोड़



रायपुर। नगर निगम में महापौर एजाज देबर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई। बैठक में 23 विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्लोबल टेंडर के स्थान पर अब जोनवार सफाई व्यवस्था का टेंडर होगा। बैठक में खराब रोड की मरम्मत के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति मिली। वहीं 10 नए एसी बसस्टॉप का निर्माण होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने टेंडर जारी किया जाएगा। कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, रोड स्वीपिंग मशीन की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 करने, दायरा 85 किलोमीटर से अतिरिक्त 62-63 किलोमीटर बढ़ाने के साथ टेंडर अविधि बढ़ाने सहमित बैठक में दी गई। इसके अलावा 193 पात्र प्रकरण निराश्रित पेंशन योजना और 38 पात्र प्रकरण परिवार सहायता योजना में स्वीकृत किए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सी मार्ट के स्थानों पर अन्य सामग्रियों के बिक्री होने से अब बैं कर पर टेंडर जारी किए जाएंगे। महापौर एजाज देबर ने बताया कि सफाई व्यवस्था पर लगातार शिकायतों के कारण अब ग्लोबल टेंडर के बाद जोनवार 1-1 टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया है।

रायपुर में गोलियों का जखीरा बरामद

रायपुर। राजधानी रायपुर में बंदूक की गोलियों का बड़ा जखीरा बरामद होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। होटल वी2 केन्यन के सामने नाले में राइफल की 70 गोलियां मिली हैं। बताया जा रहा कि ये गोलियां इंसान और एलएमजी जैसे राइफल में इस्तेमाल होती हैं। तेलीबांधा पुलिस गोलियों को जब्त कर मामलों की जांच कर रही। पुलिस के मुताबिक, ग्राम फुडहर में वीडेब्ल्यू केन्यन होटल के सामने छोकरा नाला में मछली पकड़ने वाले बच्चों को एक बिनडोरी (पाउच) में एवं खुले हुए कुछ कारतूस मिले। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नाले से कुल 84 कारतूस और दो खाली खोखा बरामद किया गया है। उक्त कारतूस में 303 बोर, एमएमके, इंसान आदि के कारतूस जब्त हुआ है। मामलों की जांच की जा रही है। ये आवाजी या अभ्यास किए जाने वाले कारतूस हैं या जिंदा कारतूस, जांच के बाद ही पता चलेगा। बताया जा रहा कि इन गोलियों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है। एसएलआर, एके-47, इंसान, श्री नॉट श्री इन बंदूकों की गोली बरामद हुई हैं।



एलुमिना प्लांट हादसा : मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की जांच शुरू

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सरगुजा जिले के मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में



रविवार को हुए औद्योगिक हादसे की जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने इस हादसे में मृत 4 लोगों के आश्रितों को 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि का चेक भी दिया। गौरतलब है कि सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुण्डा के ग्राम सिलसिला में संचालित मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में 8 सितंबर को औद्योगिक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन को घटना की त्वरित जांच और मृतकों को मुआवजा राशि देने आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की टीम ने उक्त औद्योगिक हादसे में मृत करणवीर मांझी के पिता कारु मांझी, मृत रामेश्वर मांझी की पत्नी सुनैना देवी, मृत प्रिंस राजपूत के पिता धनराज सिंह राजपूत और मृतक मनोज सिंह राजपूत की पत्नी सोनम राजपूत को 15-15 लाख रुपए का चेक उनके गृह ग्राम जाकर दिया।

प्रमुख समाचार

पहली बार फील्ड में डिजीटल क्रॉप सर्वे हुआ प्रारंभ, राज्य में बलौदाबाजार तहसील का हुआ है चयन

रायपुर। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बलौदाबाजार तहसील में डिजीटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। जिसके तहत पटवारी सहित अन्य राजस्व अधिकारी खेतों में जाकर सर्वे का कार्य पूर्ण करेंगे। इसके पूर्व जनपद पंचायत सभाकक्ष बलौदाबाजार में फील्ड में गिरदावरी अंतर्गत डिजिटल रूप से फसल का सर्वे करने वाले निजी सर्वेयर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। जिसमें बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो फ्रेंस के रूप में होगी, जो डिजिटल रूप से फसल का सर्वे

सभी खेतों में जाकर करेंगे। निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरों का टास्क दिया जायेगा। जिसे सर्वेयर खेत में जाकर लॉगिन करेगा। जो सर्वेयर को प्रारंभ करने का कार्य पूर्ण होगा। जिसमें पटवारी की भूमिका पर्यवेक्षक और राजस्व निरीक्षक की भूमिका सत्यापनकर्ता तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भूमिका जांचकर्ता अधिकारी के रूप में की गई है। सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आयेगे। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किये गए खसरे पटवारी के पास आयेगे। पटवारी या अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा दो बार रिजेक्ट होने की स्थिति

जायेगा। जो क्रॉप लगी है उसका तीन फोटो लॉनिंगट्यूट लैटिट्यूट के साथ अपलोड करना है। इस प्रकार एक नंबर का कार्य पूर्ण होगा। जिसमें पटवारी की भूमिका पर्यवेक्षक और राजस्व निरीक्षक की भूमिका सत्यापनकर्ता तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भूमिका जांचकर्ता अधिकारी के रूप में की गई है। सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आयेगे। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किये गए खसरे पटवारी के पास आयेगे। पटवारी या अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा दो बार रिजेक्ट होने की स्थिति

में आरआई के आईडी में आयेगा। ऐसे खसरों की संख्या बहुत कम होगी, जहां मौके में जाकर आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में बताया गया है कि फील्ड में क्या बोया गया है फसल की जाँस का नाम, मिश्रित फसल की स्थिति में सभी फसलों का अनुमानित रकबा, सिंचित-असिंचित फसल, एकवर्षीय या बहुवर्षीय, सोनल फसल की जानकारी आदि भरी जायेगी। सर्वेयर द्वारा साफ्टवेयर में बोये गये जाँस व एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोये गये फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टि करेगा।

जब तक साफ्टवेयर में जियोरिफ्रेंस रकबा के अनुसार सर्वे किए गए रकबा का योग एक समान नहीं आयेगा, तब तक डेटा सेव नहीं होगा। सर्वेयर किसी भी खसरा नंबर को भूमि के मेडु में खड़े होकर फोटो कैप्चर नहीं करेगा। यदि ऐसा वे करते हैं तो आपसपास के खसरा नंबर के लैटलांग मिस्टमैच होगा। इसलिए सर्वेयर प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि के अंदर कम से कम मेडु से 10 मीटर की दूरी पर जाकर प्रयोग संपादित करेगा। यदि पिछर में गेहूँ फसल दिख रहा पर सर्वेक्षक ने धान प्रविष्टि किया हो अथवा प्लाट खाली है।

राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जनता के बीच पहुंच रहे जनता का प्रतिसाद अकल्पनीय-जयंती

भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान सितंबर के प्रथम सप्ताह से ही पूरे देश में शुरू कर रहा है। प्रत्येक प्रदेश और जिला को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता सदस्य बनाने लगातार विभिन्न माध्यमों से कार्यकर्ताओं को संपर्क में हैं। अब रायपुर शहर जिला भाजपा द्वारा अध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और भाजपा से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। ज्ञात हो की रायपुर शहर जिला भाजपा को 2 लाख से

अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य प्रदान किया गया है और उल्साह से लबरज जिला भाजपा के नेता लक्ष्य से भी अधिक सदस्य बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला द्वारा रायपुर रेल्वे स्टेशन पर स्टॉल लगाकर आम नगरियों को भाजपा की सदस्यता प्रहण करवाई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती

पटेल ने कहा की की प्रदेश भाजपा द्वारा दिए गए 2 लाख सदस्यों के लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाने हमने जनता के बीच पहुंचने की योजना बनाई है और आज रायपुर भाजपा की पूरी टीम के साथ हम सभी रायपुर रेल्वे स्टेशन में आम जनता को भाजपा की सदस्यता दिलाने हेतु रायपुर विचार धारा के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे जनहितैयी कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।